mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-75 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़ 18 मार्च 2026 बुधवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

हिमाचल-बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश, गंगोत्री-यमुनोत्री में बर्फबारी

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर के राज्यों में पिछले दो दिनों से आंधी, बारिश और ओले गिर रहे हैं। IMD ने मंगलवार को पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 16 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, सिक्किम, बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। उत्तरी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मार्च में हो रही बर्फबारी से सर्दी फिर लौट आई है। बर्फबारी के कारण गुरेज-बांदीपोरा रोड, सिंथन-किश्तवाड़ रोड और मुगल रोड बंद हो गई है। वहीं जोजिला दर्रे पर बर्फ जमने से श्रीनगर-लेह हाईवे भी बंद कर दिया गया। उत्तराखंड के चमोली में सोमवार रात भी बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम का मंदिर परिसर बर्फ की मोटी चादर से ढंक गया है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ में तापमान -11डिग्री तक गिर गया है। गंगोत्री-यमुनोत्री में बर्फबारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार रात बारिश हुई और ओले भी गिरे। बिजनौर में तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए। सहारनपुर में आंधी की वजह से टीन शेड गिरने से पूर्व प्रधान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि IMD ने आज मध्य भारत के लिए यानी दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात में कोई चेतावनी नहीं दी है। यहां एक बार फिर तापमान बढ़ सकता है।

सबरीमाला मंदिर मामले में पुजारी को राहत नहीं, केरल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कोच्चि, एजेंसी। सबरीमाला मंदिर के सोना चोरी मामले में केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि मंदिर के मुख्य पुजारी (तांत्री) कंतारार राजीवर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह फैसला पुजारी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इससे मामले की कानूनी जांच फिर से शुरू हो गई है। पुजारी कंतारार राजीवर 41 दिनों तक जेल में रहने के बाद पिछले महीने ही जमानत पर बाहर आए थे। कोल्लम की निचली अदालत ने उन्हें जमानत देते समय कहा था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने इस टिप्पणी को हाई कोर्ट में चुनौती दी। जांच टीम का कहना था कि अदालत की ऐसी टिप्पणियों से चल रही जांच पर बुरा असर पड़ सकता है। एसआईटी ने मांग की थी कि इन टिप्पणियों को हटाया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके।

राजस्थान में मेगा हाईवे पर निजी बस-ट्रोला की आमने-सामने टक्कर, पांच यात्रियों की मौत

हनुमानगढ़, एजेंसी। जिले में मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। रावतसर थाना क्षेत्र में सरदारशहर रोड स्थित बरमसर के पास मेगा हाईवे पर एक निजी बस और ट्रोले की आमने-सामने भिड़ंत में पांच यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। निजी बस श्रीगंगानगर से जयपुर जा रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे सरसों से भरी दो ट्रॉलियां खड़ी थीं। बस चालक उन्हें ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रोले से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से रावतसर अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीएम संजय अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही पांच यात्रियों की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल 3-4 लोगों को हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि 7 घायलों का इलाज रावतसर अस्पताल में चल रहा है। हादसे में मारे गए पांच लोगों में से तीन मृतकों की पहचान हो चुकी है, जिनमें अजय बंसल पुत्र श्यामलाल बंसल, श्यामलाल, हरिराम पुत्र हनुमान प्रसाद हैं। ये लोग हनुमानगढ़ टाउन के रहने वाले थे। पुलिस एक महिला और पुरुष के शव की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है। हादसे में सुमन पत्नी अमित सोनी उम्र 38 साल निवासी श्रीगंगानगर, महेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश सुथार उम्र 39 साल निवासी श्रीगंगागनर, आदित्य पुत्र अशोक कौशल उम्र 17 साल, अरविन्द पुत्र हंसराज जाट उम्र 38 साल निवासी लालगढ़ जाटान और रितु नागपाल पुत्र हरीश अरोड़ा उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 18 दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन गंभीर घायल है। हादसे के वक्त अधिकतर सवारियां सो रही थी। तभी तेज धमाके की आवाज से सवारियों की नींद खुल गई। ट्रक से टकराते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई।

राज्यसभा चुनावः हरियाणा में रात तक हंगामा

ओडिशा-हरियाणा में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग

NDA ने 37 में से 22 सीटें जीतीं, 10 सीटों का फायदा

पटना, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, एजेंसी। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। सोमवार को शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी, लेकिन दो कांग्रेस विधायकों के वोटों पर भाजपा की आपत्ति के कारण रात 10.25 बजे काउंटिंग शुरू हो सकी, जो रात 1.30 बजे तक चली। वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक की प्रक्रिया में 16 घंटे लगे। ओडिशा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इससे भाजपा को फायदा मिला।

10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव में 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। इनमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गईं। विपक्ष को 2 सीटें मिलीं। तीन राज्य हरियाणा, बिहार और ओडिशा में 11 सीटों पर चुनाव हुए। एनडीए ने 22 और विपक्ष ने 15 सीटें जीतीं हैं। एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ है। पहले एनडीए के पास 12 और विपक्ष के पास 25 सीटें थीं।

चुनाव आयोग ने बंगाल के बाद केरल में अधिकारी बदलेः5 IAS-IPS का ट्रांसफर

भाजपा ने बंगाल-केरल में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

कोलकाता/तिरुवनंतपुरम/चेन्नई, एजेंसी। चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान करते ही राज्यों में अधिकारियों के तबादले शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में सोमवार में 6 अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद मंगलवार को केरल के 2 IPS और 3 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। बंगाल में दो फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। पांचों राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुवेंदु अधिकारी से सीधी टक्कर होगी। सुवेंदु अधिकारी को BJP ने नंदीग्राम और भबानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हैं। सोमवार को भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसी के साथ केरल के 140 में से 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने राज्य के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से मैदान में उतारा है।

लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा

स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा- पोस्टर और एआई से बनीं तस्वीरें न दिखाएं

नई दिल्ल, एजेंसी। लोकसभा में मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के एक सांसद हैं। ये आठ सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत-चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे।

कांग्रेस सांसद के. सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। इसके बाद ध्वनि मत से इसे पास कर दिया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका समर्थन किया। धर्मेंद यादव ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा। उन्होंने कहा कि खासकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इसका ख्याल रखें। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा,'प्लेकार्ट और एआई से बनाई गई तस्वीरें प्रदर्शित न करें।'

खड़गे का रिजिजू को लेटर- महिला आरक्षण अधिनियम पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के तरीकों और रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के प्रयास में, सरकार कानून में संशोधन के लिए संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही एक विधेयक ला सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विपक्ष को साथ लेने के लिए उनसे संपर्क साधा गया है, ताकि संसद में संविधान संशोधन विधेयक को आसानी से पारित कराया जा सके। संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद, यह विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया गया था, लेकिन यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा।

सीजेआई का सुझाव-फैमिली कोर्ट में वकील-जज काले चोंगे न पहनें

जज, वकील और पुलिस को भी यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए, इससे बच्चे डरते हैं

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि यह बहुत जरूरी है कि फैमिली कोर्ट बच्चों के मन से मनोवैज्ञानिक डर को खत्म करें। इसके लिए कोर्ट के पारंपरिक कामकाज में कुछ बदलाव किए जाएं। उन्होंने पूछा कि क्या फैमिली कोर्ट में काले चोंगे होने चाहिए? CJI ने कहा कि जब हम फैमिली कोर्ट के लिए एक नई सोच और अवधारणा बना रहे हैं तो क्या इससे बच्चे के मन में कोई मनोवैज्ञानिक डर पैदा नहीं होगा?उन्होंने सुझाव दिया कि फैमिली कोर्ट में पीठासीन जज और वकील यूनिफॉर्म में नहीं आने चाहिए। CJI सूर्यकांत ने ये बातें दिल्ली के रोहिणी में एक फैमिली कोर्ट की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट में आप सभी के लिए हमारे पीठासीन अधिकारी कोर्ट की पोशाक में नहीं बैठेंगे। बार के सदस्य भी काले और सफेद चोंगे में नहीं आएंगे। पुलिस अधिकारी भी वर्दी में नहीं आएंगे, क्योंकि यह पूरा माहौल बच्चों के मन में डर पैदा करता है, खासकर तब जब वे किसी भी व्यवस्था के सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं।

उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी की तैयारी

समिति ने सीएम भूपेंद्र पटेल को रिपोर्ट सौंपी, 24 मार्च को सदन में पेश हो सकता है विधेयक

गांधीनगर, एजेंसी। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो सकता है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। यूसीसी के लिए इस समिति का गठन 4 फरवरी, 2025 को हुआ था। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन के बाद इसने अंतिम सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गुजरात सरकार इस रिपोर्ट पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। यूसीसी विधेयक 24 मार्च को सदन में पेश किए जाने की संभावना है। महिलाओं के समान अधिकारों को प्राथमिकता मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय दिए गए विवरण में कहा गया है कि समिति ने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है।

इस मसौदे में विशेष रूप से महिलाओं के समान अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का भी ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा के बाद यूसीसी पर चर्चा तेज हुई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद गुजरात में यूसीसी पर चर्चा और तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक में केंद्र के नेताओं के साथ राज्य में यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

राज्य सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो विभिन्न धाराओं के सुझावों और कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन कर रही है। मार्च के अंतिम सप्ताह में विधानसभा सत्र में यूसीसी से संबंधित कोई प्रस्ताव या विधेयक पेश कर सकती है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक

400 की मौत,250 घायल

तालिबान का आरोप-पाक ने नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए

काबुल, एजेंसी। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुलअमान, अरजान कीमत, खैरखाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं।

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए।

तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मोशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि काबुल में किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया।

हमले से 2000 बेड वाले हॉस्पिटल को भारी नुकसान : अफगानिस्तान सरकार के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर बताया कि यह हमला स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 9 बजे हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हॉस्पिटल 2000 बेड का है। इसे भारी नुकसान हुआ है।

भारत बोला- काबुल अस्पताल पर हमला जनसंहार है

भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने इस हमले को 'कायरतापूर्ण' और 'जनसंहार' करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह एक बेहद अमानवीय और अनैतिक हिंसक कृत्य है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान गई। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि जिस जगह को किसी भी हालत में सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता, उसे निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। बयान में पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि वह इस हमले को सैन्य कार्रवाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। भारत ने कहा, पाकिस्तान का यह घिनौना हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर खुला हमला है और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। यह पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के पुराने पैटर्न को दिखाता है, जिसमें वह अपनी आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी सीमाओं के बाहर हिंसक कदम उठाता रहा है।

मिडिल ईस्ट का तेल दुनिया में सबसे महंगा, 153 डॉलर प्रति बैरल हुआ

तेल बचाने के लिए श्रीलंका में सरकारी दफ्तर सिर्फ 4 दिन खुलेंगे

तेल अवीव/तेहरान, एजेंसी। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 18वां दिन है। इस जंग के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। तेल की कीमत बढ़कर 153 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो हाल के समय में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी का असर दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, खासकर उन देशों पर जो तेल के आयात पर निर्भर हैं।तेल की कीमतों में अचानक आई इस तेजी के चलते कई देशों में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। परिवहन, बिजली और जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

इसी बीच, श्रीलंका ने घोषणा की है कि अब सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन ही खुलेंगे। यह फैसला ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी और देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी श्रीलंका आर्थिक संकट और ईंधन की कमी का सामना कर चुका है।

भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के पास दो वॉरशिप तैनात किएः भारत ने ईरान के पास मौजूद दुनिया के अहम समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट के पास अपने दो युद्धपोत तैनात किए हैं। ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय नौसेना के ये टास्क फोर्स जहाज तेल और गैस लेकर भारत आने वाले व्यापारिक जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा देंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें हर तरह की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ईद की छुट्टी में दुबई से आए नाबालिग ने एसयूवी से स्कूटर को मारी टक्कर, एक मासूम की मौत

मुंबई, एजेंसी। ईद की छुट्टियों में दुबई से मुंबई आए 17 वर्षीय नाबालिग ने चांदीवली इलाके में अपनी कार से स्कूटर में टक्कर मार दी, जिससे एक मासूम की जान चली गई। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया, जहां से उसे 27 मार्च तक के लिए सुधार गृह भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक, आरोपी नाबालिग ने चांदीवली इलाके में एक किराए की एसयूवी चलाते हुए स्कूटर को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटर पर पीछे बैठे 15 वर्षीय प्रतीक माने की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन साकीनाका पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में उसे पकड़ लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। वहां से उसे 27 मार्च तक सुधार गृह भेज दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी ने गुमराह करने की कोशिश की। उसके परिवार ने पुलिस को बताया कि वह मीरा रोड चला गया है, लेकिन बाद में वह चांदीवली में ही एक रिश्तेदार के घर छिपा हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी के दोस्त, मोहम्मद अनस मोहर्मअली खान (22) को भी नोटिस जारी किया है। उसने ही एसयूवी एक दिन के लिए किराए पर ली थी। पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है और तय करेगी कि आगे क्या कार्रवाई करनी है।इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा कि नाबालिग होने के बावजूद हादसे की गंभीरता को देखते हुए पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हादसे के शिकार बच्चे का परिवार अभीसदमे में हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। आरोपी लड़के के परिवार और अन्य दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

डबल मर्डर का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, मौके से पिस्टल और चाकू बरामद

बरेली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के बरेली में सोमवार को हुए डबल मर्डर केस का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पकड़ने आई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इज्जतनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक व्यक्ति ने अपनी ही सास और साले की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि अपनी पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पत्नी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस को सोमवार रात में सूचना मिली कि आरोपी अवैध हथियार लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में घूम रहा है और किसी और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इस इनपुट को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपी की तलाश के लिए तीन टीमें लगा दी गईं।तलाश के दौरान पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि आरोपी इसी इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने उसे घेरने और पकड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने मानने के बजाय पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लग गई। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल .32 बोर बरामद की है। साथ ही, घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। अब तक मौके से कई खोखे भी मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया जा रहा है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है। वर्ष 2009 में उसने अपने सगे मामा की हत्या की थी, जिसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसके अलावा, उसके खिलाफ चोरी और अन्य मामलों की भी जानकारी पुलिस के पास है, लेकिन अब यह पता लगाया जा रहा है कि कुल कितने मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे इलाके में मौजूद है और गहन जांच कर रही है। मौके से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और फील्ड डाटा संकलित किया जा रहा है। पुलिस एसओपी के अनुसार हर कदम उठा रही है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई सही तरीके से हो सके।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण से स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे : अमित पटेल

वाराणसी, एजेंसी। ग्राम पंचायत रमना स्थित ग्राम सचिवालय में दो दिवसीय मुख्यमंत्री ग्राम स्वरोजगार खाद्य प्रसंस्करण योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान अमित पटेल ने किया। उन्होंने कहा कि किसान खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेकर स्वयं का रोजगार स्थापित कर लाभ कमा सकते हैं। प्रशिक्षण में मीरा जायसवाल ने योजना के अंतर्गत उद्यमियों को मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी। वहीं, राजकीय फल संरक्षण केंद्र बीएचयू वाराणसी के पूर्व प्रभारी व पूर्व जिला खाद्य प्रसंस्करण प्रभारी ने बेकरी, तेल, आटा, अचार, पापड़, मिठाई और सॉस जैसे उद्योग स्थापित करने के बारे में बताया। डीआरपी विक्की जायसवाल ने उद्योग स्थापना के प्रोजेक्ट व ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझाई। अनुराधा सिंह, सहायक ग्राम पंचायत रमना ने फल-सब्जियों को सुरक्षित रखने में खाद्य प्रसंस्करण की उपयोगिता बताई। प्रशिक्षण में 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 30 प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान प्रशिक्षुओं को संतरा स्क्वैश बनाकर उसका स्वाद भी कराया गया। संचालन सुपरवाइजर अरुण कुमार सिंह ने किया।

कानपुर के निवेशकों पर मिडिल ईस्ट वॉर की गाज ; डूबे 10,000 करोड़, कोविड जैसे बने हालात

कानपुर, एजेंसी। कानपुर में पश्चिम एशिया संकट ने शहर के निवेशकों को भी तगड़ा झटका दिया है। इसके अलावा चढ़ने और गिरने वाले शेयरों के अनुपात (एडवांस-डिक्लाइन रेशियो) में तेज गिरावट आई है। फरवरी 2026 में यह अनुपात 1.01 प्रतिशत था, जो घटकर 0.71 हो गया है। इसका मतलब है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में चढ़ने वाले शेयरों की संख्या घटी है और गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों की संख्या बढ़ी है। इसके पहले कोविड काल के मार्च 2020 का यह अनुपात 0.72 दर्ज किया गया था, जो मौजूदा स्तर से थोड़ा ही अधिक है। इस बीच शहर में लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले निवेशकों ने बाजार से दूरी बना ली है। युद्ध के चलते एनएसई कैश सेगमेंट में शहर के औसत कारोबार में भी तेज गिरावट आई है। यह जनवरी-फरवरी के 265 करोड़ से घटकर 200 करोड़ रुपये रोजाना के करीब ही रह गया है। पोर्टफोलियो वैल्यू में भी 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के गिरावट का अनुमान है। वहीं, पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से निफ्टी-50 में करीब आठ फीसदी की गिरावट आई है। फरवरी के तीसरे सप्ताह में निफ्टी लगभग 25,885 के उच्च स्तर था। सोमवार को यह 23,408.पर बंद हुआ है। कोविड काल में निफ्टी में सबसे तेज गिरावट आई थी जो निफ्टी-50 सूचकांक जनवरी 2020 में 12,430.50 के उच्च स्तर पर था।

मई में अनुपात 1.21 और जून में 1.09 रहा : वह लॉकडाउन के बाद तेजी से लुढ़का और 24 मार्च 2020 को 7,511.10 के निचले स्तर पर पहुंच गया। जनवरी के शिखर के मुकाबले यह गिरावट लगभग 39.6 प्रतिशत थी। 23 मार्च 2020 को एक ही दिन में उसमें 13 प्रतिशत की गिरावट आई थी। यह गिरावट इतनी तेज थी कि डाउन सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ गया था। बीएसई में पर चढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों का अनुपात इस समय साल के सबसे निचले स्तर (0.71) पर है। एक साल पहले अप्रैल 2025 में यह अनुपात 1.26 था। अप्रैल 2025 में 2509 शेयर चढ़े थे, जबकि 1996 शेयरों में गिरावट आई थी। इसके बाद मई में यह अनुपात 1.21 और जून में 1.09 रहा।

अनुपात गिरकर 0.71 रह गया : लेकिन जुलाई और अगस्त में यह घटकर 0.95 और 0.94 पर आ गया, जिससे पता चलता है कि चढ़ने वाले शेयरों की संख्या घटने वाले शेयरों से कम हो गई। सितंबर और अक्तूबर में कुछ सुधार देखा गया।

ममता की सीट से सुवेंदु को टिकट, दिग्गज नेताओं पर भाजपा ने जताया भरोसा; किसे कहां से मिला टिकट

कोलकाता, एजेंसी। बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ममता बनर्जी बनाम सुवेंदु अधिकारी का मुकाबला तय है। भाजपा ने राज्य की 144 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा के महज 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सोमवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे चौंकाने वाला और बड़ा नाम राज्य के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का है। भाजपा ने आक्रामक तरीके से उन पर बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें एक साथ दो हाई-प्रोफाइल सीटों–नंदीग्राम और कोलकाता के भवानीपुर–से मैदान में उतारा है। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पारंपरिक गढ़ ही नहीं बल्कि इसी क्षेत्र में उनका निवास स्थान भी है। ऐसे में सुवेंदु की वहां से उम्मीदवारी ने एक बार फिर 'ममता बनाम सुवेंदु' की सीधी जंग की जमीन तैयार कर दी है। इसी के साथ भाजपा ने एक बार फिर ममता को उन्हीं के गृह क्षेत्र में घेरने की रणनीति अपनाई है। 2021 में ममता ने नंदीग्राम में सुवेंदु को घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन हार गई थीं। भाजपा की जारी सूची में कई पुराने और चर्चित चेहरों को दोबारा मौका दिया गया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को एक बार फिर खड़गपुर सदर से मैदान में उतारा गया है। वहीं, पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता को दक्षिण कोलकाता के

अहम रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। हावड़ा जिले में भी भाजपा ने कुछ चर्चित नामों पर भरोसा जताया है। हावड़ा की शिवपुर सीट से अभिनेता-राजनेता रुद्रनील घोष को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बराहनगर से सजल घोष और हावड़ा उत्तर से उमेश राय को टिकट दिया गया है। इस बार भी पार्टी ने अपने अधिकांश मौजूदा विधायकों पर भरोसा कायम रखा है और पहली सूची में कई परिचित चेहरों को शामिल किया गया है।

सामाजिक समीकरणों का समावेश : पार्टी ने अपनी पहली सूची में भौगोलिक और सामाजिक संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। उत्तर बंगाल के चाय बागान क्षेत्रों से लेकर दक्षिण बंगाल के जंगलमहल तक, पार्टी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति अपनाई है। प्रथम सूची में 32 एससी और 13 एसटी प्रत्याशी हैं। वहीं 11 महिलाओं उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है, जिनमें से कई मौजूदा विधायक हैं।

बालुरघाट से नया चेहरा : हालांकि, कुछ सीटों पर बदलाव भी देखने को मिला है। बालुरघाट सीट से मौजूदा विधायक व अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को टिकट नहीं दिया गया है और उनकी जगह विद्युत राय को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह गोघाट के वर्तमान विधायक विश्वनाथ कारक और आरामबाग के विधायक मधुसूदन बाग को भी टिकट नहीं मिला। इन दोनों सीटों से क्रमशः प्रशांत दिगर और हेमंत बाग को उम्मीदवार बनाया गया है।

कई मौजूदा विधायकों को टिकट : मौजूदा विधायकों में आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पाल को फिर से टिकट मिला है, जबकि बांकुड़ा जिले की शालतोड़ा सीट से चंदना बाउरी को भी दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। जलपाईगुड़ी के डाबग्राम-फुलबाड़ी से शिखा चट्टोपाध्याय और कूचबिहार के तुफानगंज से मालती रावा राय को भी पार्टी ने फिर मौका दिया है। इसके अलावा कूचबिहार उत्तर से सुकुमार राय, कुमारग्राम से मनोज ओरांव, कालचीनी से विशाल लामा, फालाकाटा से दीपक बर्मन और नागराकाटा से पुना भेंगरा को भी उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी से आनंदमय बर्मन, फांसीदेवा से दुर्गा मुर्मू, तपन से बुधराय टुडू, गंगारामपुर से सत्येंद्रनाथ राय, हबीबपुर से जुएल मुर्मू, गाजोल से चिन्मय देवबर्मन और दुर्गापुर पश्चिम से लक्ष्मण घोरुई को भी टिकट दिया गया है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की कुमारगंज सीट से भाजपा के प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष शुभेंदु सरकार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में उम्मीदवार बदला गया है और मौजूदा विधायक सौमेन राय की जगह उत्पल महाराज को टिकट दिया गया है। बीरभूम के सिउड़ी से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है। मुर्शिदाबाद जिले में भाजपा ने पिछली बार जीती दोनों सीटों पर अपने विधायकों पर भी भरोसा बरकरार रखा है। बहरमपुर से सुब्रत मैत्रा और मुर्शिदाबाद से गौरीशंकर घोष को फिर मैदान में उतारा गया है। बेलडांगा से अधीर चौधरी के पूर्व करीबी माने जाने वाले और बेलडांगा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भरत झावर को टिकट दिया गया है। नदिया जिले के रानाघाट की दोनों सीटों से विधायक पार्थसारथी चट्टोपाध्याय और असीम विश्वास को फिर मौका मिला है। वहीं डायमंड हार्बर से पूर्व विधायक दीपक कुमार हलदार को भी भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। हुगली जिले के पुरशुड़ा और खानाकुल से क्रमशः विधायक बिमान घोष और सुषांत घोष फिर अपनी ही सीटों से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण हलदार को उम्मीदवार बनाया गया है।

कामचोरी और सीनाजोरी... गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी से कतरा रहे सर्जन, अब होगी कार्रवाई

गाजियाबाद, एजेंसी। जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात अधिकांश सर्जन सर्जरी करने से बचते हैं। इतना ही नहीं सर्जरी कम करने पर कई सर्जन की किरकरी भी हो रही। दस से अधिक सर्जन को इस संबंध में नोटिस जारी किये गये हैं।जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में रिपोर्ट देखकर एक सर्जन ने अधिकारियों से सीनाजोरी भी की। इस सर्जन की एक माह की रिपोर्ट के कालम में शून्य लिखा हुआ था। उच्चाधिकारी इस सर्जन की पूरी कुंडली खंगलवा रहे हैं। इसके साथ ही कम सर्जरी करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 28 फरवरी को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिले भर के सर्जन की सर्जरी का ब्यौरा रखा गया। 21 दिसंबर 2025 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक माइनर एवं मेजर सर्जरी के साथ ही अप्रैल 2025 से 20 जनवरी 2026 तक की गई कुल सर्जरी का विवरण प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के अनुसार संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में तैनात डा. शिवनाथ सिंह, डा. एके सिंह, डा.मनीष मित्तल और 50 बेडेड संयुक्त अस्पताल डूंडाहेडा में कार्यरत डा. अतुल आनंद,डा.सुनील कुमार,डा.सुषमा शर्मा और डा. मदन लाल की सर्जरी बेहद कम देखकर अधिकारी नाराज हुए। सीएमओ डा. अखिलेश मोहन का कहना है कि उक्त चिकित्सकों को नोटिस जारी करते हुए सुधार का समय दिया गया है। सुधार न होने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। अनुबंध के तौर पर कार्यरत चिकित्सकों का अनुबंध खत्म करने पर विचार किया जायेगा। बता दें कि कई चिकित्सक सर्जरी से संबंधित मरीजों को हायर सेंटर रेफर करना बेहतर मानते हैं।

निमोनिया के इलाज में एआई की एंट्री, एम्स-दिल्ली और स्वीडन मिलकर खोजेंगे तेज

नई दिल्ली, एजेंसी। निमोनिया जैसी सांस की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाओं की खोज को तेज करने के उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। स्वीडन के प्रमुख शोध संस्थानों के साथ एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के लिए संस्थान को इंडो-स्वीडिश सहयोग कार्यक्रम के तहत डीबीटी-विनोवा से शोध अनुदान प्राप्त हुआ है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी की मदद से ऐसे पेप्टाइड आधारित चिकित्सीय तकनीक विकसित करनी है, जो निमोनिया पैदा करने वाले रोगाणुओं से प्रभावी ढंग से लड़ सकें।

पारंपरिक दवा खोज प्रक्रिया में

वर्षों का समय लगता है, लेकिन एआई आधारित तकनीकों से संभावित दवाओं की पहचान और परीक्षण की प्रक्रिया कहीं अधिक तेज और किफायती हो सकती है। परियोजना के तहत भारत और स्वीडन के वैज्ञानिक मिलकर मशीन लर्निंग मॉडल तैयार करेंगे, जो संभावित पेप्टाइड दवाओं की रोगाणुरोधी क्षमता, एलर्जी प्रभाव और विषाक्तता जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं का अनुमान लगाने में सक्षम होंगे।

इसके बाद इन कम्प्यूटेशनल भविष्यवाणियों को प्रयोगशाला में परीक्षण के जरिए सत्यापित किया जाएगा, जिससे दवा के प्रभाव और सुरक्षा का आकलन किया जा सके।

इस शोध परियोजना का नेतृत्व आईआईआईटी-दिल्ली के डॉ. अरुल मुरुगन मुख्य अन्वेषक के रूप में कर रहे हैं, जबकि प्रो. जीपीएस राघव और डॉ. विभोर कुमार सह-अन्वेषक हैं। स्वीडन की ओर से केटीएच रायल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉ. वैभव श्रीवास्तव और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के डॉ. उज्ज्वल न्योगी इस शोध में सहयोग कर रहे हैं। परियोजना के लिए भारत की ओर से लगभग 52.2 लाख रुपये और स्वीडन की ओर से 2.8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का वित्तीय सहयोग दिया गया है। इस पहल से दोनों देशों के शोधकर्ताओं और छात्रों के बीच वैज्ञानिक सहयोग और अकादमिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई और प्रयोगशाला परीक्षण के संयोजन से दवा खोज की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। यह पहल न केवल निमोनिया बल्कि अन्य संक्रामक और श्वसन संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए भी नई संभावनाएं खोल सकती है।

इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने में माहिर है हमारा पड़ोसी

यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा

भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और उसके फर्जी प्रोपेगैंडा की पोल खोलकर रख दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि भारत का पश्चिमी पड़ोसी अपनी धार्मिक पहचान को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथनेनी हरीश ने कहा, 'भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहते हैं। साथ ही, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे चार प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई है।

ऐसे में भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में धार्मिक भेदभाव से मुक्त दुनिया की जरूरत को ज्यादा बेहतर समझता है। भारतीय राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र को भी आईना दिखाते हुए कहा, 'संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पना एक ऐसे संस्थान के रूप में की गई थी जो धर्म, संस्कृति और राजनीति से ऊपर उठकर काम करे।

इसलिए हम ऐसे किसी भी ढांचे को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर देते हैं, जो केवल एक धर्म पर ध्यान दे और धार्मिक भय (रिलिजियोफोबिया) की व्यापक समस्या पर ध्यान न दे। उन्होंने कहा, हमारे विचार में 1981 का 'धर्म या आस्था के आधार पर सभी प्रकार की असहिष्णुता और भेदभाव के उन्मूलन संबंधी घोषणा' एक संतुलित दस्तावेज है, जो किसी एक धर्म को विशेष महत्व दिए बिना सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

ईयू के नेताओं के साथ जयशंकर ने की व्यापार, वैश्विक मुद्दों पर वार्ता

उर्सुला वॉन डेर लेयेन से की मुलाकात

वॉशिंगटन, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ (ईयू) के उच्च नेता और विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुए भारत-यूरोपीय संघ समझौतों को लागू करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। जयशंकर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने सोमवार को ईयू की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कल्लास के निमंत्रण पर यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। विदेश मंत्रियों ने दोनों पक्षों के बीच हुए विभिन्न समझौतों को ठोस परिणामों में बदलने पर चर्चा की।

हमारी बातचीत में विशेष रूप से व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, आवागमन और रक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने कहा कि नेताओं ने पश्चिम एशिया संघर्ष, यूक्रेन की स्थिति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्री ने बेल्जियम में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी मुलाकात की। इस वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया और यूक्रेन में हाल की घटनाओं पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने लेयेन के समकालीन वैश्विक घटनाओं पर दृष्टिकोण की सराहना की। मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात की जानकारी साझा की।

ईरान मिसाइल क्षमता ध्वस्त होने के अमेरिकी दावों के बीच जारी भीषण हमले, ड्रोन-मोबाइल लॉन्चर बने बड़ी चुनौती

दोहा/वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और इस्राइल का दावा है कि संयुक्त हमलों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके कई लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं।

इसके बावजूद ईरान अब भी क्षेत्रीय देशों और इस्राइल की दिशा में असरदार तरीके से मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान की हमला क्षमता जरूर घटी है, लेकिन उसके पास अभी भी इतने हथियार और वैकल्पिक रणनीतियां मौजूद हैं कि वह सीमित लेकिन रणनीतिक हमलों के जरिये पूरे क्षेत्र में तनाव बनाए रख सकता है।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि

अभियान एपिक फ्यूरी में ईरान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता कार्यात्मक रूप से नष्ट हो चुकी है, उसकी नौसेना को युद्ध के लिहाज से अप्रभावी माना जा रहा है और अमेरिकी व इस्राइली वायुसेना ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इन दावों के बावजूद सोमवार को कतर ने घोषणा की कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने भी मिसाइल अलर्ट जारी किए।

अबू धाबी में एक मिसाइल के कार पर गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी वजह यह है कि ईरान की पूरी क्षमता खत्म नहीं हुई है। उसके पास अभी भी मिसाइलों का बड़ा भंडार, मोबाइल लॉन्चर और विकेंद्रीकृत सैन्य ढांचा मौजूद है, जिससे वह सीमित स्तर पर हमले जारी रख सकता है।

हमले कम हुए पर लगा रहा सटीक निशाना : रिपोर्ट के अनुसार हालांकि युद्ध के शुरुआती दिनों की तुलना में ईरान के हमलों में स्पष्ट कमी आई है। संघर्ष के पहले 24 घंटों में ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात की ओर 167 मिसाइलें और 541 ड्रोन दागे थे।

लेकिन युद्ध के 15वें दिन यह संख्या घटकर सिर्फ 26 मिसाइल और करीब 50 ड्रोन रह गई, यह आंकड़े यूएई के रक्षा मंत्रालय के बयानों के आधार पर संकलित किए गए हैं। इस्राइल पर हमलों में भी गिरावट आई है। शुरुआती दो दिनों में लगभग 100 प्रोजेक्टाइल दागे गए थे, जबकि हाल के दिनों में यह संख्या 15 से 20 सिमट गई है।पेंटागन ने भी कहा कि युद्ध के पहले दिन की तुलना में ईरानी मिसाइल लॉन्च 90 प्रतिशत और ड्रोन हमले 86 प्रतिशत तक घट गए हैं।

ईरान के पास क्षेत्र का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार : अमेरिकी खुफिया एजेंसी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने 2022 में आकलन किया था कि ईरान के पास क्षेत्र का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है। हालांकि इसकी सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इस्राइली खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पास लगभग 3000 मिसाइलें थीं। पिछले साल जून में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद यह संख्या घटकर लगभग 2500 रह गई थी।

प्रशासनिक फेरबदल, प्रिया पाठक बनीं सीएमओ

एसडीएम से नायब तहसीलदारों तक के तबादले; कलेक्टर ने जारी किए आदेश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने सोमवार को बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत एसडीएम, नायब तहसीलदार और प्रभारी अधिकारियों सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर नई पदस्थापनाएं की गई हैं। इस बदलाव को प्रशासनिक कार्यों में गति लाने यह कदम माना जा रहा है।

आदेश के अनुसार, सिहावल की एसडीएम प्रिया पाठक को नगर पालिका परिषद सीधी का मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) बनाया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय नगर पालिका परिषद सीधी में प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और तेज गति से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

यहां हुई अदला-बदली

वहीं चुरहट के एसडीएम शैलेश द्विवेदी को एसडीएम कुसमी बनाया गया है। तो कुसमी में पदस्थ एसडीएम विकास कुमार आनंद को अब एसडीएम चुरहट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों अधिकारियों की अदला-बदली को प्रशासनिक अनुभव के बेहतर उपयोग के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, गोपाल बनास के एसडीएम राकेश शुक्ला को उनके वर्तमान पद के साथ एसडीएम सिहावल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वे अब दोनों क्षेत्रों की प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।

नायब तहसीलदार और प्रभारी नायब तहसीलदारों के कार्य का विभाजन

कलेक्टर ने नायब तहसीलदार और प्रभारी नायब तहसीलदारों के बीच भी व्यापक स्तर पर कार्य विभाजन किया है। आदेश के अनुसार, वेदवती सिंह को कलेक्टर कार्यालय सीधी की सीएम हेल्पलाइन शाखा में नोडल अधिकारी और धनकुवर टौप्पो को उसी शाखा में सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। अमित कुमार दुबे को तहसील गोपदबनास के वृत्त गिर्द-द्वितीय, परमसुख बंसल को तहसील रामपुर नैकिन के वृत्त रामपुर और महेंद्र कुमार द्विवेदी को तहसील कुसमी के वृत्त पोंड़ी में प्रभारी नायब तहसीलदार पद पर पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा जयप्रकाश पाण्डेय को तहसील सिहावल का प्रभारी तहसीलदार, उपेन्द्र कुमार द्विवेदी को वृत्त भुईमाड़ तहसील कुसमी, गणेश प्रसाद पाण्डे को वृत्त जोवा तहसील मझौली, दीनबन्धु प्रजापति को तहसील चुरहट, मनोज कुमार द्विवेदी को वृत्त कुबरी तहसील बहरी तथा हंसराज सिंह को वृत्त गिजवार तहसील मड़वास में प्रभारी नायब तहसीलदार के रूप में पदस्थ किया गया है।

भूमि अधिग्रहण के विरोध में कांग्रेस का धरना

गोल्ड-बेस मेटल परियोजना के नाम पर जमीन बचाने की मांग

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के बगैया गांव में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन गोल्ड एवं बेस मेटल परियोजना के नाम पर हो रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में था। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए, जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरस्वती सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को कंपनियों को सौंपने में लगी है। सिंह ने चेतावनी दी कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम और पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने भी इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने बताया कि चितरंगी और दूधमनिया तहसील के कई गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिससे गरीब और आदिवासी परिवारों के सामने विस्थापन का खतरा उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में प्राइवेट कंपनी के नाम पर अधिग्रहित की गई जमीन पर उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। उनका कहना था कि किसानों को उनकी जमीन भी वापस नहीं मिली है। धरना प्रदर्शन के दौरान, नेताओं ने मांग की कि प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा, बेहतर पुनर्वास और संबंधित कंपनियों में स्थायी रोजगार प्रदान किया जाए। इस कार्यक्रम में लल्ला राम पांडेय, नरेंद्र चंद्र सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे।

नेशनल हाईवे पर पाताल जैसी सुरंग, 50 से ज्यादा पत्थर डालने पर भी नहीं भरी; 2 दिन में 3 हादसे, पीडब्ल्यूडी ने कहा- हमारा क्षेत्र नहीं

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी के अमिलई गांव से गुजरने वाले नेशनल हाईवे (एनएच-39) के बीचो-बीच अचानक सड़क धंस गई। गहरी सुरंग जैसे बने इस गड्ढे में दो दिन में तीन बड़े हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सुरंग पाताल जैसी गहरी है। समय रहते इसे नहीं भरा गया तो बड़े हादसा हो सकते हैं।

गांव के तेज बहादुर सिंह ने बताया कि उन्होंने सुबह करीब 50 से ज्यादा बड़े पत्थर इस सुरंग में डाले, लेकिन गड्ढा नहीं भरा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सड़क के नीचे काफी गहराई है। ग्रामीणों ने इस स्थिति को विभागीय लापरवाही का नतीजा बताया है।

सूचना के बाद भी अधिकारियों ने नहीं की कार्रवाई: ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को इस खतरे के बारे में जानकारी दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि एनएच-39 से जुड़े अधिकारी जिले में कम ही उपलब्ध रहते हैं, जिससे शिकायतें उन तक नहीं पहुंच पातीं। मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारी कौशल परते ने बताया कि यह सड़क उनके विभाग ने नहीं बनाई है, इसलिए वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इससे सड़क की मरम्मत को लेकर विभागों के बीच जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है।

ग्रामीण ने खुद लगाया चेतावनी झंडा: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को गांव के लोगों ने खुद पहल करते हुए गड्ढे को कपड़ों से ढंक दिया और पास में लकड़ी का डंडा गाड़कर उस पर चेतावनी झंडा लगा दिया, ताकि राहगीर सतर्क रह सकें और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

अपर कलेक्टर बोले- जल्द ही सुरंग भरवाएंगे: सीधी के अपर कलेक्टर बीपी पांडे ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिल गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर जल्द ही इस खतरनाक सुरंग को भरवाने का आश्वासन दिया है।

अलग-अलग हादसों में 5 लोग हो चुके घायल: ग्रामीणों को सड़क धंसने की जानकारी शनिवार सुबह 11 बजे लगी। रात में दो बाइक सवार हादसे के शिकार हो गए, जिन्हें शहडोल जिले के देवलोंद अस्पताल भेजा गया था। दूसरा हादसा सोमवार सुबह 9 बजे हुआ है। इन हादसों में कुल पांच लोग घायल हुए थे।

स्कूल के बाहर छात्रों से मारपीट, बाइक सवार बदमाशों ने पीटा; छात्रों ने भी की पत्थरबाजी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सेमरिया के सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर छात्रों के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बाइक सवार कुछ बदमाश लगभग 6 से ज्यादा छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटते हुए दिख रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। यह घटना स्कूल के मुख्य गेट के बाहर हुई बताई जा रही है। हमले के जवाब में छात्रों ने भी पत्थरबाजी की, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग गए। इस मारपीट में दो छात्रों को चोटें आई हैं। उन्हें सेमरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने स्कूल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। मारपीट की प्रारंभिक वजह आपसी विवाद बताई जा रही है, हालांकि इसके वास्तविक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।

प्राचार्य को नहीं जानकारी: स्कूल के प्राचार्य अनिल मिश्रा ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी क्योंकि वे मूल्यांकन कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।

शिकायत पर कार्रवाई करेंगे: सेमरिया थाना प्रभारी केदार परौहा ने पुष्टि की कि उन्होंने भी वीडियो देखा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। स्कूल प्रबंधन से चर्चा के बाद मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

जल गंगा संवर्धन अभियान हेतु सभी जनपद पंचायतों में प्रशिक्षण आयोजित

सीधी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 19 मार्च 2026 को भारतीय नववर्ष प्रतिपदा (गुड़ी पड़वा) के अवसर पर उज्जैन स्थित शिप्रा नदी तट से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सोलंकी के निर्देशन में 19 मार्च से प्रारंभ होने वाले इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले की सभी जनपद पंचायतों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह जल गंगा संवर्धन अभियान 100 दिवसीय जन-अभियान है, जिसका उद्देश्य राज्य की नदियों, तालाबों, कुओं एवं बावड़ियों का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करना है।

जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत ने सुनी 122 आवेदकों की समस्याएं

निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए 122 आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने प्रत्येक आवेदन पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली तथा शीघ्र एवं पारदर्शी निराकरण के निर्देश दिए।

सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन आवेदनों में समय-सीमा निर्धारित है, उन्हें विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ लेते हुए तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही हितग्राही को समय पर सूचना देना भी अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों पर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्रवाई की जाए, जिससे आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।

इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास राकेश शुक्ला सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे।

अडाणी प्लांट में आगजनी के लिए जांच टीम बनाई

मजदूरों ने कलेक्टर से की थी शिकायत, तीन दिन में रिपोर्ट मांगी

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के बधौरा स्थित अडाणी पावर प्लांट में शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर गौरव बैनल ने विशेष जांच टीम का गठन किया है। यह कदम प्लांट परिसर में तोड़फोड़, आगजनी और श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन के बाद उठाया गया है। मजदूरों ने श्रम कानूनों के उल्लंघन को लेकर कई गंभीर शिकायत की थी। इनमें समय पर वेतन न मिलना, ओवरटाइम का भुगतान न होना, श्रमिकों के साथ लापरवाहीपूर्ण व्यवहार और श्रम नियमों का पालन न करना शामिल है। इन्हीं शिकायतों के कारण मजदूरों में आक्रोश बढ़ा और यह मामला हंगामे में बदल गया।

लगभग 5 घंटे तक चले इस उपद्रव के दौरान प्लांट में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद ही हालात सामान्य हो सके। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गठित जांच दल श्रमिकों के नियोजन, वेतन भुगतान, ओवरटाइम, रहन-सहन और औद्योगिक सुरक्षा मानकों के पालन की विस्तृत जांच करेगा। टीम को तीन दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिव्यांग छात्रों का प्रेरणादायी एक्सपोजर भ्रमण सम्पन्न, एक्सपोजर विजिट से बढ़ा आत्मविश्वास और उत्साह

परसिली रिसॉर्ट में विद्यार्थियों ने लिया प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह के निर्देशन एवं एडीपीसी ओशो उत्सव के मार्गदर्शन में शासकीय हाईस्कूल एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के दिव्यांग छात्रों का एक्सपोजर भ्रमण 15 मार्च को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह एक्सपोजर भ्रमण विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिसके माध्यम से उन्हें विद्यालयीन वातावरण से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त करने, नए परिवेश को समझने तथा अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर मिला। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश पर्यटन के प्रसिद्ध परसिली रिसॉर्ट का भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर सीधी जिले के सभी विकासखंडों से दिव्यांग छात्र उत्साहपूर्वक शामिल हुए। सभी छात्र अपने मार्गदर्शी शिक्षकों के साथ पीएम श्री विद्यालय चमराडोल में एकत्रित हुए, जहां प्रारंभ में परिचय सत्र आयोजित किया गया। परिचय सत्र में प्राचार्य अशोक तिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायी गीत जीना है तो हंस कर जियो ने विद्यार्थियों में ऊर्जा और उत्साह का संचार किया, वहीं प्रिया शुक्ला के मधुर गीत ने सभी को आनंदित किया। इसके उपरांत छात्र परसिली रिसॉर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। पार्क में झूलों का आनंद लेते हुए छात्र अत्यंत प्रसन्न दिखाई दिए। भ्रमण के पश्चात सभी छात्र पुनः चमराडोल लौटे, जहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। यह सम्पूर्ण कार्यक्रम एपीसी रमसा डॉ. सुजीत मिश्रा के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की सफलता में प्राचार्य अशोक तिवारी, राजकुमार सिंह, कृष्ण गिरि, शैलेन्द्र सिंह (पथरौला), बालेन्दु शेखर दुबे, पुष्पराज सिंह, रामअनुग्रह मिश्रा, प्रभाकर तिवारी, रचना टांडिया, प्रिया शुक्ला एवं स्पेशल एजुकेटर्स का विशेष योगदान रहा।

कलेक्टर-कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई

गनियारी पीजी कॉलेज की भूमि से हटा अतिक्रमण, 15 मकानों को बुलडोजर चलाकर किया जमींदोज

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिला मुख्यालय के पास गनियारी में पीजी कॉलेज के लिए आरक्षित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मंगलवार को प्रशासन का बुल्डोजर चला। तहसीलदार सविता यादव के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम ने करीब 15 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शेष बचे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

2024 से लंबित था बेदखली का आदेश: राजस्व विभाग के अनुसार, गनियारी की इस कीमती जमीन पर लगभग तीन दर्जन लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्के मकान बना लिए थे। इस संबंध में 15 मार्च 2024 को ही बेदखली आदेश पारित हो चुका था, लेकिन अमल अब जाकर हुआ है। प्रशासन ने 12 मार्च को अंतिम नोटिस जारी कर 16 मार्च तक कब्जा हटाने की मोहलत दी थी, जिसके बाद मंगलवार को यह बड़ी कार्रवाई की गई।

कमिश्नर-कलेक्टर के निरीक्षण के बाद सख्ती: हाल ही में रीवा संभाग आयुक्त बी.एस. जामोद और कलेक्टर गौरव बैनल ने ?26.91 करोड़ की लागत से निर्मित पीजी कॉलेज भवन का निरीक्षण किया था। परिसर के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण देख कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए इसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे। इसी निर्देश के परिपालन में तहसीलदार सविता यादव और पटवारी उमेश नामदेव की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। लोगों ने बताया कि ध्वस्त किए गए कई मकानों में बिजली कनेक्शन और अमृत जल योजना की पाइपलाइन पहले से मौजूद थी। कुछ रहवासियों का दावा है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान स्वीकृत हुए थे। लोगों ने सवाल उठाया कि जब निर्माण हो रहा था, तब नगर निगम या राजस्व विभाग ने उन्हें क्यों नहीं रोका।

महिला से मारपीट, पीड़िता बोली- सरकारी जमीन विवाद में पूर्व सरपंच समेत दो लोगों ने पीटा

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के जियावान थाना क्षेत्र में कुछ लोग एक महिला को पीटते नजर आ रहे हैं। यह पूरा विवाद सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बताया जा रहा है। वीडियो 6 मार्च का बताया जा रहा है। पीड़ित महिला उमा देवी सोनी का आरोप है कि पूर्व सरपंच (नौडिया आबाद) और आरएसएस के एक प्रदेश पदाधिकारी के भाई भगवान दास गुप्ता ने उनके साथ मारपीट की है।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: पीड़ित महिला का कहना है कि उन्होंने घटना वाले दिन यानी 6 मार्च को ही जियावान थाने में शिकायत की थी। उनका आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कदम उठाती, तो उनके साथ यह बदसलूकी नहीं होती। महिला के मुताबिक, रसूख के चलते अब तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है।

वीडियो के आधार पर जांच शुरू: मामला बढ़ने पर देवसर एसडीओपी गायत्री मिश्रा ने बताया कि मारपीट का वीडियो उनके संज्ञान में मंगलवार को ही आया है। उन्होंने जियावान थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को वीडियो की बारीकी से जांच करने और विवाद की असली वजह पता करने के निर्देश दिए हैं। एसडीओपी ने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस गांव के लोगों

जन्मदात्री की रक्षा: पंजाब-हरियाणा में मातृ-स्वास्थ्य को गंभीरता से लें

संपादकीय

हालांकि, पंजाब में पिछले दिनों सामने आए मातृ स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े कुछ हद तक उम्मीद जरूर जगाते हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्य में बच्चे को जन्म देने के दौरान मातृ मृत्यु दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। जो निश्चित रूप से गर्भावस्था और प्रसव के दौरान माताओं की सेहत की सुरक्षा करने में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता में क्रमबद्ध सुधार का ही संकेत देती है। लेकिन, इस मामूली गिरावट के बावजूद एक गंभीर चिंता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि प्रगति अभी भी धीमी व असमान गति वाली है। दरअसल, मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों के रूप में मापी जाती है। जिसे व्यापक अर्थों में किसी भी समाज की स्वास्थ्य सेवा की क्षमता तथा समाज में लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण सूचक भी माना जाता है। इस तरह मातृ मृत्यु दर में आई मामूली गिरावट भी प्रसव पूर्व गर्भवती स्त्री की देखभाल, संस्थागत स्तर पर प्रसव कराने और आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की स्थिति में सुधार को ही दर्शाती है। इसके बावजूद अभी पंजाब में मातृ स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार की काफी गुंजाइश है। विशेष रूप से तब जब कि कई जिलों में मातृ मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। यहां जरूरी हो जाता है कि पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाए। हालांकि, पहले इस दिशा में आशातीत प्रगति दर्ज की गई थी। लेकिन अब हरियाणा की मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर के नवीनतम मूल्यांकन चक्र में स्थिति लगभग अपरिवर्तित ही नजर आती है। निश्चित तौर पर आंकड़ों में देखी जा रही यह स्थिरता सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में एक आम चुनौती को ही उजागर करती है। निर्विवाद रूप से प्रारंभिक स्तर पर किए गए सुधार अक्सर त्वरित लाभ देते हैं, लेकिन जरूरी है कि इस दिशा में प्रगति को अनवरत बनाया रखा जाए। निस्संदेह, इस प्रगति के लिये निरंतर गहन संरचनात्मक परिवर्तनों की जरूरत होती है। वास्तव में मातृ स्वास्थ्य रक्षा के लिये कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में केवल अस्पतालों और योजनाओं में निवेश करना ही पर्याप्त नहीं होता है। बल्कि गर्भावस्था के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल, समय रहते रेफरल और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निरंतर निगरानी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल, पंजाब में स्वास्थ्य संबंधी ऑडिट से पहले ही प्रणालीगत खामियों की ओर संकेत मिला है। जैसा कि निदान में देरी, प्रसवोत्तर रक्तस्राव जैसी जटिलताओं का खराब प्रबंधन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच कमजोर समन्वय का होना भी है।

एप्पल के संस्थापक का 'पागलों' को सलाम

सनत जैन

एप्पल के 50 साल पूरे होने पर दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल के प्रमुख टिम कुक ने एक प्रेरणादायक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, समाज जिन लोगों को पहिले 'पागल' और असफल मानती है, वही लोग अक्सर दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। उनके अनुसार अलग सोच और समाज के लिए बड़े बदलाव का नया प्रयोग ही भविष्य की जरूरत और सामाजिक बदलाव का समय के अनुसार रास्ता तैयार करता है। उन्होंने कहा, एक छोटे से विचार बनी बड़ी कंपनी एप्पल की शुरुआत हुई थी। बाद में इस सोच के साथ अन्य साथी जिसमें स्टीव जॉब्स और उनके साथियों ने तकनीक की दुनिया में कई नए कल्पनाशील प्रयोग किए। समय के बदलाव के साथ कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उत्पादों के माध्यम से एप्पल इंच ने पूरी दुनिया में तकनीकी बदलाव लाने में विश्व स्तर पर बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इस पर सभी को गर्व है। अलग सोच ही इतिहास बनाती है। टिम कुक का मानना है, जो लोग परंपराओं से हटकर नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी वह नई सोच एक नया इतिहास बनाती हैं। कई बार समाज ऐसे लोगों को अलग या असामान्य मानता है। वह अपनी सोच के अनुसार जब काम करते हैं उसके परिणाम मिलने में कई साल लग जाते हैं ऐसी स्थिति में परिवार के लोग, मित्र और अन्य उन्हें या तो पागल समझने लगते हैं या असफल मानने लगते हैं। यही लोग अपनी सोच की प्रतिबद्धता के कारण समाज के लिए नए रास्ते तैयार करते हैं। नई संभावनाएं पैदा करते हैं। जो समाज के बदलाव में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। टिम कुक ने युवाओं को संदेश दिया है, अगर उनके पास कोई नया विचार है। उसे आगे बढ़ाने का साहस धैर्यपूर्वक और सतत करते हैं। शुरुआत में लोग उस विचार को भले समझ नही पाते हैं, लेकिन वही सोच आगे चलकर दुनिया को बदलने का कारण बन जाती है। टिम कुक के अनुसार नवाचार, साहस और अलग नजरिया ही भविष्य को बेहतर बनाते हैं। एप्पल के संस्थापक का यह संदेश बताता है, कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। जब वह एक बड़े बदलाव के लिए सोचता है तो वह अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव को समाज के लिए लाने की सोच पर काम करता है। यही सोच उसे दूसरों से अलग करती है। वह अपनी सोच को वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए हर संभव एकाग्रता के साथ प्रयास करता है। उसे इस दौरान कई असफलताएं मिलती हैं, लेकिन यही असफलताएं उन्हें असाधारण सफलता में बदलने का कारण बनती है। हर व्यक्ति की अलग सोच होती है, हर व्यक्ति का दायरा अलग होता है और जब वह पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उस पर काम करना शुरू करता है तो परिणाम भी उसके अनुसार मिलना शुरू हो जाते हैं। तकनीकी के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट एप्पल और अन्य की इस तरह की जो सफलतायें हैं वह आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बिना पूंजी, बिना संसाधन अपनी सोच के अनुसार काम करने, धैर्य रखने, बार-बार की असफलताओं से भी निरुसाहित नहीं होने से उन्हें सफलता मिलती है। यही उनकी सफलता का प्रमाण है। वर्तमान संदर्भ में जब डिग्री से रोजगार की कल्पना हमारा युवा वर्ग कर रहा है ऐसे समय पर एप्पल माइक्रो सॉफ्ट और अन्य सफलतम व्यक्ति तथा संस्थान से आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी होगी। जिस तरह से पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपने करियर को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता है उसके लिए सतत प्रयास करता है। निश्चित रूप से उसे उसकी सफलता मिलती है। यही एप्पल के संस्थापक का संदेश है।

हाल ही में, यानी कि 13 मार्च 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड लीव (मासिक धर्म अवकाश) को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल,भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बात कही है कि इस तरह की नीति को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। वास्तव में इस क्रम में अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यदि इस प्रकार का प्रावधान कानून के रूप में लागू किया गया, तो कई नियोक्ता महिलाओं को रोजगार देने से ही हिचक सकते हैं, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने पेड पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका सुनने से ही इंकार कर दिया और इस मुद्दे पर व्यावहारिक चिंताओं को सामने रखा।

मेंस्ट्रुअल लीव (मासिक धर्म अवकाश): सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वैश्विक परिप्रेक्ष्य !

सुनील कुमार महला

यहां पाठकों को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग की गई थी कि देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली शारीरिक परेशानियों को देखते हुए हर महीने कुछ दिनों का अवकाश दिया जाए। याचिका में यह तर्क दिया गया कि गर्भावस्था के लिए तो अवकाश का प्रावधान किया गया है, लेकिन मासिक धर्म से जुड़ी तकलीफों के लिए कोई सार्वभौमिक व्यवस्था नहीं है। साथ ही, यह भी कहा गया कि कुछ राज्यों और कई निजी कंपनियों में महीने में दो दिन के पीरियड लीव का प्रावधान किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को ऐसे नियम बनाने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. आर. शमशाद ने यह भी बताया कि केरल सरकार ने स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू की है और देश की कई निजी कंपनियाँ भी स्वेच्छा से पेड पीरियड लीव दे रही हैं।मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि कोई कंपनी अपनी इच्छा से पीरियड्स के दौरान छुट्टी दे रही है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही इसे कानून के रूप में सख्ती से लागू किया जाएगा, उसके दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना होगा। अदालत ने आशंका व्यक्त की कि ऐसा प्रावधान अनिवार्य होने पर संभव है कि नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से बचने लगें। इससे महिलाओं को सरकारी नौकरियों, न्यायपालिका या अन्य पेशों में अवसर मिलने में कठिनाई हो सकती है और उनका करियर प्रभावित हो सकता है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कई बार ऐसी याचिकाएँ एक तरह का डर पैदा करती हैं और यह संदेश देती हैं कि जैसे मासिक धर्म महिलाओं के साथ होने वाली कोई नकारात्मक या असाधारण घटना है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह कहा है कि महिलाओं को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि इस प्रकार की मांग कार्यस्थल पर महिलाओं के विकास और उनकी परिपक्वता को लेकर गलत मानसिकता भी पैदा कर सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता पहले ही अपनी मांग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष रख चुके हैं, इसलिए सरकार सभी हितधारकों से चर्चा कर इस विषय पर कोई नीति बनाने पर विचार कर सकती है। अदालत ने संबंधित प्राधिकरणों को यह सुझाव दिया कि वे इस अभ्यावेदन पर विचार करें और विभिन्न पक्षों से परामर्श करके नीति का प्रारूप तैयार करें। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी कहा कि विचार अच्छा हो सकता है, लेकिन नियोक्ताओं के पक्ष को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें पेड लीव देने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। वास्तव में, इस पूरे मुद्दे पर समाज और महिलाओं के बीच भी अलग-अलग मत सामने आए हैं। कई महिलाओं का मानना है कि उन्होंने दशकों के संघर्ष के बाद कार्यस्थल पर बराबरी का अधिकार प्राप्त किया है। ऐसे में विशेष अवकाश की अनिवार्यता उन्हें पुरुषों की तुलना में कमजोर या कम सक्षम दिखा सकती है। कॉर्पोरेट संस्कृति में अक्सर उपलब्धता को सफलता का पैमाना माना जाता है, इसलिए महीने में निश्चित छुट्टी लेने वाली महिला को महत्वपूर्ण परियोजनाओं या नेतृत्व की भूमिकाओं से बाहर रखा जा सकता है। कुछ महिलाओं का यह भी मानना है कि अनिवार्य पीरियड लीव के कारण कई संस्थान महिलाओं के बजाय पुरुषों को अधिक प्राथमिकता देने लगेंगे, जिससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कई महिलाएँ सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत भी कर रही हैं।वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाओं का यह मानना है कि इस विषय में एक संतुलित या मध्य मार्ग होना चाहिए। उनके अनुसार पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने के बजाय वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का विकल्प दिया जाना चाहिए। इससे महिला का काम भी प्रभावित नहीं होगा और उसे कार्यालय के तनावपूर्ण वातावरण से राहत भी मिल सकेगी। उनका यह भी मानना है कि इस प्रकार की व्यवस्था से महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उनकी पेशेवर गरिमा भी बनी रहेगी। दरअसल कई महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान दर्द, ऐंठन, मतली और माइग्रेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लगातार काम करना उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन हो सकता है। इसलिए कुछ महिलाओं का कहना है कि पीरियड लीव का उद्देश्य भले ही नेक और संवेदनशील है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, जिससे महिलाओं की व्यावसायिक गरिमा और नौकरी की सुरक्षा पर कोई आंच न आए।बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि विश्व के कई देशों में पीरियड लीव (मासिक धर्म अवकाश) को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रावधान मौजूद हैं, हालांकि इसकी व्यवस्था हर देश में एक जैसी नहीं है। गौरतलब है कि कुछ देशों ने इसे श्रम कानून का हिस्सा बनाया है। जबकि कुछ स्थानों पर इसे कुछ कंपनियों या संस्थानों द्वारा अपनी इंटरनल पालिसी के रूप में लागू किया गया है।उदाहरण के लिए नाइके और भारत की कंपनी जौमेटो ने भी महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव की नीति लागू की है। यहां यदि हम देशों की बात करें तो जापान में वर्ष 1947 से ही महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश लेने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी महिला कर्मचारी को पीरियड के दौरान काम करने में कठिनाई होती है, तो वह छुट्टी ले सकती है, हालांकि यह छुट्टी वेतन सहित होगी या नहीं, यह कंपनी की नीति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया में महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की मेंस्ट्रुअल लीव का अधिकार प्राप्त है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया के श्रम कानून में भी महिलाओं को मासिक धर्म के पहले दो दिनों में अवकाश लेने की अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं, अफ्रीकी देश जांबिया में मदर्स डे लीव के नाम से हर महीने एक दिन की पीरियड लीव दी जाती है, जिसके लिए चिकित्सकीय प्रमाणपत्र की आवश्यकता भी नहीं होती। हाल के वर्षों में स्पेन ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2023 में पेड पीरियड लीव को कानूनी मान्यता प्रदान की, जिससे गंभीर मासिक धर्म पीड़ा से पीड़ित महिलाएं चिकित्सकीय सलाह के आधार पर अवकाश ले सकती हैं। बहरहाल, यहां कहना ग़लत नहीं होगा कि इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर पीरियड लीव को लेकर एकरूपता नहीं है, लेकिन मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य और गरिमा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों और संस्थानों में इसके प्रति जागरूकता और नीतिगत पहल लगातार बढ़ रही है। अंत में यहां पर निष्कर्ष के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि पीरियड लीव का मुद्दा केवल अवकाश देने या न देने का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह कार्यस्थल पर समानता, संवेदनशीलता और व्यावहारिकता के बीच संतुलन खोजने का विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए यह संकेत दिया गया है कि किसी भी नीति को लागू करते समय उसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि महिलाओं को कमजोर मानकर विशेष प्रावधान बनाने के बजाय ऐसे समाधान तलाशे जाने चाहिए जो उनकी गरिमा, अवसरों की समानता और पेशेवर विकास को प्रभावित न करें।इस संदर्भ में कई महिलाओं की राय है कि अनिवार्य पीरियड लीव के बजाय फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स या वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अधिक व्यावहारिक हो सकते हैं। इससे एक ओर महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली शारीरिक असुविधा से कुछ राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर उनके करियर, आत्मविश्वास और पेशेवर अवसरों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आज के समय में आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, संस्थान और समाज मिलकर ऐसा संतुलित और संवेदनशील मॉडल विकसित करें, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और कार्यस्थल पर समान अवसर-तीनों को साथ लेकर आगे बढ़े।

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।)

इन बेगुनाह मासूम स्कूली बच्चियों के खून का कौन जिम्मेदार?

ईरान में एक स्कूल में 165 बच्चियां क्लास पढ़ाई के लिए मौजूद थी लेकिन उन्हे इस बात का गुमान नही रहा होगा कि प्रभुत्व की सनक में दुनिया के कथित ताकतवर देश की अंधी मिसाइल उनके जीवन का खात्मा कर देंगी। स्कूल पर हुए मिसाइल हमले को लेकर अब पेंटागन की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में स्थित शजराह तैय्यबेह स्कूल पर हुआ हमला दरअसल अमेरिकी सेना की एक गंभीर गलती का नतीजा था। जांच के मुताबिक अमेरिकी सेना उस इलाके में एक ईरानी नौसैनिक ठिकाने को निशाना बना रही थी।

मनोज कुमार अग्रवाल

माना जाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआइ ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में काम को काफी आसान बना कर अच्छा अनुभव दिया है। मैडिकल, लीगल और एजुकेशन जैसे सैक्टर्स में डाटा संग्रहण और त्वरित गणना की सुविधा से कई अच्छे कार्य हो रहे हैं लेकिन इसी बीच ईरान युद्ध के दौरान अमरीका द्वारा किए गए ए. आई. के इस्तेमाल और इस निशाने में हुई चूक के कारण हुई स्कूली बच्चियों की मौत ने दुनिया में दहशत की इबारत लिख ममदी है।

शुरुआती जांच में माना गया है कि यह हमला जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि खुफिया जानकारी और टार्गेटिंग सिस्टम में हुई चूक के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद अमेरिकी सैन्य तंत्र के अंदर भी टार्गेटिंग प्रक्रिया और डेटा की सटीकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस हमले को लेकर जो खुलासा सामने आ रहा है उसमे गंभीर चूक का अनुमान है पुरानी इंटेलिजेंस की वजह से शायद अमेरिका ने ईरान के एक एलिमेंट्री स्कूल पर जानलेवा मिसाइल हमला किया, जिसमें लड़ाई के शुरुआती घंटों में 165 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। स्कूल पर बमबारी और उसमें बच्चों की मौत युद्ध का मुख्य मुद्दा बन गई है। अगर यह कन्फर्म हो जाता है कि यह यूएस के हाथों हुआ था, तो यह पिछले दो दशकों में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से हुई सबसे ज्यादा आम लोगों की मौत की घटनाओं में से एक होगी।

दरअसल अग्रणी ए.आई. कंपनी एंथ्रोपिक ने इस साल जनवरी ही में पेंटागन के उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, जिसके तहत अमरीकी सेना को सभी वैध उद्देश्यों के लिए उसकी तकनीक तक असीमित पहुंच मिल जाती। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए, एंथ्रोपिक के सी.ई.ओ. डारियो अमोदेई ने 2 स्पष्ट शर्तें रखीं- अमरीकियों की बड़े पैमाने पर जासूसी नहीं की जाएगी और मानवीय निगरानी के बिना पूरी तरह से स्वायत्त हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से एंथ्रोपिक को भारी नुकसान हुआ, परन्तु प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने तुरंत पेंटागन के साथ मानव नियंत्रण के बिना पूर्ण ए.आई. नियंत्रण के लिए समझौता कर लिया। इस समझौते के बाद अमरीका और इसराईल ने ईरान के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर दिया। युद्ध के पहले ही दिन 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके 10 टॉप कमांडरों की हत्या उनके परिसर में कर दी गई, जिसे दोनों देशों ने ए.आई. पर्शियन हमले की एक बड़ी जीत माना।लेकिन उसी दिन, 28 फरवरी को, एक और घातक हमला मीनाब में स्थित शजराह तैयबा गर्ल्स स्कूल पर भी किया गया। 2 मिसाइलों ने 45 सैकेंड में स्कूल को नष्ट कर दिया था। मीनाब में जो हुआ, वह ए.आई. के अंधाधुंध उपयोग का सबसे भयावह उदाहरण है।

यह एक अक्षम्य पाप है जब शजराह तैयबा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, जिसमें 165 से अधिक मासूम बच्चियां मौत से लड़ती, चीखती-चिल्लाती रहीं, तकनीकी भाषा में इसे सटीक हमला कहा गया। जबकि ट्रम्प यह दावा कर रहे हैं कि लड़कियों के स्कूल पर ईरान ने टोमहॉक मिसाइल से हमला किया था, जबकि सभी जानते हैं कि ईरान के पास यह मिसाइल नहीं है, यहां तक कि इसराईल के पास भी नहीं है, इसलिए उनके द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाए गए झूठ से सच को छिपाने का काम किया जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, बाद में कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि कौन दोषी है, और फिर कहा कि वह पेंटागन की जांच के नतीजों को मान लेंगे। यह हाल ही में यह मामला और ज्यादा पेचीदा हो गयी जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार रिपोर्ट किया कि शुरुआती जांच में पाया गया कि यूएस जिम्मेदार है। शुरुआती नतीजों के बाद पेंटागन से तुरंत और जानकारी मांगी गई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि जांच अभी भी चल रही है।

28 फरवरी को शजारेह तैयबेह एलिमेंट्री स्कूल पर हुआ हमला, जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास के बेस के पास है। हमले के लिए अमेरिका की जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हुए सबूत बढ़ रहे हैं। ऐसे कई संकेत हैं जिससे पता चलता है कि स्कूल पर हमला टाला जा सकता था। ये हमले 28 फरवरी की सुबह हुए थे। तब स्कूल की बिल्डिंग छोटे बच्चों से भरी हुई थी। न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि स्क और उसी दिन हमले वाले दूसरे टारगेट, हवा से दिखने वाली ऐसी खासियतें थीं जिनसे हमले से पहले उन्हें सिविलियन साइट के तौर पर पहचाना जा सकता था। इस हमले के वीडियो में एक्सपर्ट्स ने अमेरिका में बनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को मिलिट्री कंपाउंड में टकराते हुए देखा जा सकता है। जबकि उस इलाके से पहले से ही धुआं उठ रहा था जहां स्कूल था।

पब्लिक में मौजूद सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि स्कूल बिल्डिंग लगभग 2017 तक मिलिट्री कंपाउंड का हिस्सा थी, जब दोनों को अलग करने के लिए एक नई दीवार बनाई गई। प्रॉपर्टी पर एक वॉचटावर भी हटा दिया गया था। उसी समय की तस्वीरों से पता चलता है कि बिल्डिंग के चारों ओर की दीवारों पर चमकीले रंगों, खासकर नीले और गुलाबी रंग के म्यूरल बनाए गए थे। ये इतने चमकीले थे कि वे स्पेस से भी दिखाई देते हैं। स्कूल को ऑनलाइन मैप पर साफ तौर पर लेबल किया गया था और इसकी एक आसानी से मिलने वाली वेबसाइट है जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में जानकारी भरी हुई है।

युद्ध को कंट्रोल करने वाला इंटरनेशनल कानून उन स्ट्रक्चर्स, गाड़ियों और लोगों पर हमले करने से रोकता है जो मिलिट्री के निशाने और लड़ाके नहीं हैं। आम लोगों के घर, स्कूल, मेडिकल और सामाजिक जगहें आम तौर पर मिलिट्री हमलों के लिए बंद रहती हैं।

बताया जा रहा है कि यह सारा मामला एआइ की चूक से हुआ है दरअसल 10 साल पहले इस क्षेत्र पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आई.आर.जी.सी.) ईरानी सशस्त्र बलों का एक सैन्य परिसर था।लेकिन डाटाबेस अपडेट न होने के कारण ए.आई. को यह मालूम नहीं पड़ा कि अब उसी स्थान पर बाई ओर एक अस्पताल और दाई तरफ एक अलग प्रवेश द्वार वाला स्कूल मौजूद है।

ए.आई. एल्गोरिद्म यह भी समझने में नाकाम रहा कि 7 से 12 साल की बच्चियां दुश्मन नहीं होतीं। एक मशीन के लिए वे केवल कोलेटरल डैमेज थीं। यह घटना साबित करती है कि जब हम युद्ध का पूर्ण नियंत्रण ए. आई. को देते हैं, तो हम युद्ध के मैदान से दया और विवेक को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं।ए.आई. आधारित व्यापक निगरानी हमारी मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए गंभीर और नए प्रकार के खतरे पैदा कर सकती है।

किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्च ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि उन्नत ए. आई. मॉडल्स युद्ध की स्थिति में 95 प्रतिशत बार परमाणु विकल्प या अत्यधिक आक्रामकता को चुनते हैं। मशीनों के लिए जीत ही एकमात्र लक्ष्य है, चाहे उसकी कीमत पूरी दुनिया का विनाश ही क्यों न हो। अगर हम आज ए.आई. को रक्षा क्षेत्र और समाज में खुली छूट देते हैं, तो हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां युद्ध का फैसला जनरल नहीं, बल्कि एक कोडिंग प्रोग्राम करेगा।

जीवन के बाद भी जीवन, अंगदान के संकल्प से जगेंगी कई उम्मीदें

मनेन्द्रगढ़ के अनिल केसरवानी बने मिसाल, मानवता को दी नई दिशा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कभी-कभी एक व्यक्ति का लिया गया निर्णय समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत लहर पैदा कर देता है। जिले में ऐसा ही एक प्रेरक उदाहरण सामने आया है, जहां मनेन्द्रगढ़ के प्रतिष्ठित नागरिक अनिल केसरवानी ने अपनी मृत्यु के पश्चात अंगदान करने का संकल्प लेकर मानवता के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। 16 मार्च 2026 को उन्होंने मेडिकल कॉलेज एमसीबी की अधिष्ठाता डॉ. रंजना आर्या के समक्ष अंगदान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर अपने इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया। यह पहल न केवल एक व्यक्तिगत संकल्प है, बल्कि उन अनगिनत जरूरतमंद मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण है, जो अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से जीवन पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति का अंगदान कई लोगों को नया जीवन दे सकता है। ऐसे में केसरवानी का यह कदम सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। उनका यह निर्णय यह संदेश देता है कि जीवन की सीमाओं के बाद भी इंसान दूसरों के जीवन में उजाला भर सकता है। जिले में प्रस्तावित नए चिकित्सा महाविद्यालय के संदर्भ में भी यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंगदान और देहदान चिकित्सा शिक्षा की आधारशिला माने जाते हैं। इनके माध्यम से मेडिकल छात्र मानव शरीर की संरचना, बीमारियों और उपचार की बारीकियों को व्यावहारिक रूप से समझ पाते हैं। स्वेच्छा से किया गया देहदान भविष्य के चिकित्सकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार संभव होता है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंगदान एवं देहदान के महत्व को समझें और इस पुनीत कार्य में सहभागिता निभाएं। अनिल केसरवानी की यह पहल समाज के लिए एक सशक्त संदेश है– 'जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन इंसानियत हमेशा जीवित रहती है।' उनका यह संकल्प आने वाले समय में न केवल कई जिंदगियों को नया जीवन देगा, बल्कि समाज में जागरूकता, सहयोग और मानवता की भावना को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

आधार कैंप, आधार बेस्ड उपस्थिति और ई-ऑफिस पर कलेक्टर सख्त : प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित सेवा वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित समय-सीमा की वर्चुअल बैठक में कलेक्टर ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। बैठक में आधार कैंपों के विस्तार, आधार बेस्ड उपस्थिति प्रणाली के अनिवार्य क्रियान्वयन और ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जिला पंचायत, नगर निगम, एसडीएम एवं तहसील कार्यालयों सहित सभी शासकीय कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविदा, नियमित एवं अन्य सभी कर्मचारियों की उपस्थिति इसी प्रणाली से दर्ज की जाए, जिससे पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित हो सके। आधार नामांकन और अद्यतन कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने दूरस्थ, आदिवासी और वंचित क्षेत्रों में नियमित रूप से विशेष आधार कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति आधार सेवाओं से वंचित न रहे, इसके लिए विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास विभाग को आधार किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। ई-ऑफिस प्रणाली को प्रशासनिक दक्षता का प्रमुख माध्यम बताते हुए कलेक्टर ने फाइलों के डिजिटल निस्तारण और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही न्यायालयीन प्रकरणों, विशेषकर उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। बैठक में भूमि आवंटन नालंदा परिसर के लिए भूमि चिन्हांकन स्कूल भवनों की स्वीकृति खेल विभाग हेतु भूमि चयन और प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए समय-सीमा में योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए, ताकि जिले में विकास की गति बनी रहे और आमजन को त्वरित लाभ मिल सके।

बाल मधुमेह पर जागरूकता की मजबूत पहल, 130 स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण बना उम्मीद की नई किरण

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में बच्चों के स्वास्थ्य भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय और सकारात्मक पहल के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग एवं यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 16-17 मार्च को बाल मधुमेह पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। यह पहल विशेष रूप से टाइप-1 डायबिटीज (बाल मधुमेह) की समय पर पहचान और बेहतर प्रबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। कार्यशाला में जिले भर से आए 130 स्वास्थ्य कर्मियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और समन्वयकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रतिभागियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति उनकी जागरूकता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को टाइप-1 डायबिटीज के लक्षणों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार, काउंसलिंग, रोगी सहायता समूहों की भूमिका, मानसिक स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यावहारिक जानकारी दी गई। समूह गतिविधियों और अनुभव साझा करने के माध्यम से प्रतिभागियों ने विषय की गहराई से समझ विकसित की, जिससे भविष्य में बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने इस पहल को बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। प्रशिक्षण का संचालन यूनिसेफ की टीम द्वारा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. राजेंद्र रॉय, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. विनीत, जिला नोडल अधिकारी डॉ. नम्रता चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारियों का सक्रिय सहयोग रहा। कार्यक्रम की निरंतरता में 18 एवं 19 मार्च को जनकपुर एवं मनेन्द्रगढ़ में भी ऐसे ही उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षित हो सकें। जिला स्वास्थ्य विभाग ने विश्वास जताया है कि इस तरह की पहल से बाल मधुमेह की समय पर पहचान और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा तथा आने वाले समय में जिले के बच्चों का स्वास्थ्य अधिक सुरक्षित और सशक्त बन सकेगा।

पहली बार रोबोटिक सर्जरी, स्वास्थ्य शिविर में देश का पहला हर्निया ऑपरेशन सिंधिया ने देखी पूरी प्रक्रिया

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी जिले में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में पहली बार आधुनिक रोबोटिक तकनीक का उपयोग कर एक हर्निया मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया है, जिसे देश के किसी भी स्वास्थ्य शिविर में होने वाली पहली अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी माना जा रहा है। शिविर में उपचार के लिए आए हर्निया मरीज का यह सफल ऑपरेशन प्रसिद्ध सर्जन डॉ. मेहक भंडारी और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, यह मिनिमली इनवेसिव (कम चीरे वाली) सर्जरी तकनीक है, जिसे एक सटीक और सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है। इस अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से मरीज को कम दर्द का अहसास होता है और उसे तेजी से ठीक होने में मदद मिलती है। सिंधिया ने किया सर्जरी का अवलोकन केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस स्वास्थ्य शिविर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की पूरी प्रक्रिया का करीब से अवलोकन किया और डॉक्टरों की टीम के प्रयासों की सराहना की। विश्वस्तरीय सुविधाएं अबह्य दूरस्थ क्षेत्रों में भी सिंधिया ने कहा, 'स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक का उपयोग समय की आवश्यकता है, और ऐसे शिविरों के माध्यम से इसे आम जनता तक पहुंचाना एक प्रशंसनीय कदम है।' उन्होंने आगे कहा, 'विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं अब दूरस्थ क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो रही हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।'

संभाग स्तरीय सरगुजा ओलम्पिक के लिए 311 खिलाड़ी होंगे रवाना

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के खिलाड़ियों के लिए एक गौरवपूर्ण अवसर सामने आया है। संभाग स्तरीय सरगुजा ओलम्पिक 2025-26 का आयोजन 21 से 23 मार्च 2026 तक अम्बिकापुर में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में जिले के तीनों विकासखंडों से कुल 311 खिलाड़ी उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे विकासखंड मनेन्द्रगढ़ से 152, खड़गवां से 125 और भरतपुर से 34 खिलाड़ी इस आयोजन में भाग लेंगे सभी खिलाड़ी 20 मार्च को स्वामी आत्मानंद विद्यालय मनेन्द्रगढ़ से दोपहर 12 बजे बस के माध्यम से अम्बिकापुर के लिए रवाना होंगे यह आयोजन न केवल खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा, बल्कि जिले में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देगा।

संघर्ष से सम्मान तक : कपड़ा दुकान ने बदली गायत्री गुप्ता की दुनिया

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी से जूझ रही ग्राम पंचायत तिलौली (विकासखंड भरतपुर) की गायत्री गुप्ता आज आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की मिसाल बन चुकी हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने दृढ़ संकल्प से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने परिवार को भी नई दिशा दी गायत्री के जीवन में एक समय ऐसा था जब वे आर्थिक समस्याओं से घिरी रहती थीं। घरेलू जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को साकार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। इसी दौरान उन्होंने 'शेरावाली महिला स्व सहायता समूह' से जुड़कर बदलाव की शुरुआत की। समूह से उन्हें 70 हजार रुपये का ऋण मिला, जिसने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई इस आर्थिक सहयोग से गायत्री ने अपने गांव में कपड़ों की छोटी दुकान शुरू की। शुरुआती दौर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा-ग्राहकों की कमी, सीमित अनुभव और संसाधनों की कमी। लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की, ग्राहकों का विश्वास जीता और धीरे-धीरे उनका व्यवसाय बढ़ता गया आज उनकी दुकान गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक भरोसेमंद पहचान बन चुकी है। इस व्यवसाय से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 87 हजार रुपये की आय हो रही है, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतों को आत्मसम्मान के साथ पूरा कर पा रही हैं। बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्च और बचत-सभी में सुधार आया है। आर्थिक मजबूती के साथ-साथ गायत्री के आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जो महिला कभी संकोच में रहती थीं, आज वही अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उनकी सफलता से प्रेरित होकर कई महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। गायत्री गुप्ता की यह कहानी साबित करती है कि मजबूत इरादों और सही अवसर के साथ कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। यह ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल है।

महतारी वंदन से बदली तकदीर, मुन्नी बाई ने बकरी पालन से लिखी आत्मनिर्भरता की नई कहानी

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता अब केवल सहयोग नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रही है। इसी कड़ी में विकासखंड भरतपुर के ग्राम बड़गांवखुर्द की निवासी मुन्नी बाई ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को नई दिशा दी है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मुन्नी बाई को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है। उन्होंने इस राशि को खर्च करने के बजाय बचत कर, अपनी ओर से कुछ धन जोड़कर बकरी पालन का छोटा व्यवसाय शुरू किया। सीमित संसाधनों से शुरू हुआ यह प्रयास आज उनकी मेहनत और लगन से एक स्थायी आय का माध्यम बन चुका है। शुरुआत में कुछ बकरियों से आरंभ हुआ यह कार्य अब धीरे-धीरे विस्तार ले रहा है। वर्तमान में वे नियमित आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुन्नी बाई बताती हैं कि पहले वे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, लेकिन अब वे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है उनकी सफलता से प्रेरित होकर गांव की अन्य महिलाएं भी योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

डिजिटल दौर में बदली तस्वीर : फैंसी स्टोर से प्रीति यादव बनीं आत्मनिर्भर उद्यमी

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। तेजी से बदलते डिजिटल दौर में जहां आत्मनिर्भरता सफलता की नई पहचान बन रही है, वहीं विकासखंड भरतपुर के ग्राम तिलौली की प्रीति यादव ने अपनी सोच और मेहनत से एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने साबित किया कि आधुनिक दृष्टिकोण और मजबूत इरादों के साथ गांव में रहकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। साधारण परिवार से आने वाली प्रीति यादव के सामने भी आर्थिक चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अवसर तलाशा। 'दुर्गा महिला स्व सहायता समूह' से जुड़कर उन्होंने न केवल आर्थिक सहायता प्राप्त की, बल्कि आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हासिल की। समूह से मिले 60 हजार रुपये के ऋण से प्रीति ने अपने गांव में चूड़ी, कॉस्मेटिक्स और फैंसी आइटम का स्टोर शुरू किया। उनकी विशेषता यह रही कि उन्होंने अपने व्यवसाय को आधुनिक सोच के साथ जोड़ा। ग्राहकों की पसंद को समझते हुए उन्होंने ट्रेंडिंग उत्पाद उपलब्ध कराए और त्योहारों पर विशेष कलेक्शन पेश किया, जिससे उनकी दुकान युवाओं और महिलाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई। आज उनका स्टोर गांव में एक 'ट्रेंडिंग शॉप' के रूप में पहचान बना चुका है। इस व्यवसाय से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 80 से 85 हजार रुपये की आय हो रही है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अब वे बच्चों की शिक्षा और भविष्य की योजनाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रही हैं। प्रीति यादव की सफलता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की कहानी भी है। उनकी प्रेरणा से कई महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं यह कहानी दर्शाती है कि आधुनिक सोच, सही अवसर और मेहनत के साथ ग्रामीण महिलाएं भी नए भारत की सशक्त उद्यमी बन सकती हैं।

शिशु संरक्षण माह का भव्य शुभारंभ : बच्चों को विटामिन 'ए' व आयरन सिरप पिलाकर अभियान की शुरुआत

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित 220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में मंगलवार को शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बच्चों को विटामिन 'ए' एवं आयरन फोलिक एसिड सिरप पिलाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। साथ ही जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर जिलेभर में जनजागरूकता अभियान का आगाज किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. विनीत विश्वकर्मा, अस्पताल अधीक्षक डॉ. स्वप्निल तिवारी, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.एस. सिंह, डीपीएम शिशिर जायसवाल एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नोडल अधिकारी अवनीश पाण्डेय विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि शिशु संरक्षण माह का उद्देश्य बच्चों को कुपोषण एनीमिया और विभिन्न संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखना है। विटामिन 'ए' बच्चों की दृष्टि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, वहीं आयरन फोलिक एसिड सिरप बच्चों में खून की कमी को दूर करने में सहायक होता है यह अभियान विशेष रूप से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र विकास को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों में ले जाकर आवश्यक दवाएं एवं पोषण सेवाएं अवश्य दिलाएं। उन्होंने बताया कि इस माह के दौरान टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण परामर्श और आवश्यक दवाओं का वितरण एक साथ किया जाएगा जिससे बच्चों को समग्र स्वास्थ्य लाभ मिल सके। जागरूकता रथ के माध्यम से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को बच्चों के पोषण स्वच्छता टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी ताकि अधिक से अधिक परिवार इस अभियान से जुड़ सकें। कार्यक्रम में आरएमएनसीएच सलाहकार सुषमा पाण्डेय, बीपीएम संतोष नायक, वरुण मिश्रा सहित अस्पताल के अधिकारी-कर्मचारी एवं अन्य नागरिक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने इसे जनभागीदारी से सफल बनने वाला अभियान बताया।

कोषालय में बिल जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च वित्त विभाग ने जारी किए अहम निर्देश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिला कोषालय अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के सभी देयकों के समयबद्ध निराकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने देयक कोषालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित सभी देयकों को कोषालय एवं उप कोषालय में जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 तय की गई है। वहीं, एसएनए-स्पर्श के माध्यम से होने वाले भुगतानों के लिए देयक स्वीकृति की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 25 मार्च तक प्रस्तुत देयकों पर यदि कोई आपत्ति आती है, तो उसके निराकरण के बाद पुनः प्रस्तुत किए गए देयकों पर भी यही समय-सीमा लागू रहेगी। हालांकि, 25 मार्च के बाद जारी नई स्वीकृतियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कुछ विशेष श्रेणियों के देयकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, जिनमें केंद्रांश, विधायकों के स्वत्व, राजभवन, विधानसभा, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित देयक शामिल हैं। विभाग ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 25 मार्च को शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन पेमेंट फाइल जनरेट कर लें तथा समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

पुलिस चेकिंग से शराब तस्करों के मंसूबों पर फिर पानी: रात 3 बजे खड़ी गाड़ी देख पहुंची पुलिस

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम के मीनाक्षी चौक पर मंगलवार तड़के 3 बजे पुलिस ने एक संदिग्ध टवेरा गाड़ी से 75 लीटर अवैध शराब जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात 3 बजे मीनाक्षी चौक पर गुजरात पासिंग टवेरा गाड़ी (ळछ्-18क्ष्न्-7820) संदिग्ध हालत में खड़ी थी। गाड़ी में तीन युवक बैठे थे, जिन्हें देखकर एसआई महेश जाट, आरक्षक अजय मदकोरिया और सतीश ने पूछताछ की।पुलिस ने ड्राइविंग सीट पर बैठे विनोद कीर से इतनी रात को वहां खड़े होने का कारण और नाम-पता पूछा तो तीनों घबरा गए।

तलाशी में मिली 6 पेटी अवैध शराब : संदेह होने पर पुलिस टीम ने टवेरा गाड़ी की जांच की। गाड़ी के पीछे 6 पेटी शराब रखी मिली, जिसमें 24 केन बियर और देशी शराब शामिल थी। पुलिस द्वारा शराब के संबंध में दस्तावेज मांगने पर आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके।

27 हजार की शराब और 3 लाख की गाड़ी जब्त : पुलिस ने मौके से कुल 75 लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 27 हजार रुपए है। शराब परिवहन में इस्तेमाल की जा रही 3 लाख रुपए कीमत की टवेरा गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, यह शराब सांगाखेड़ा क्षेत्र से अवैध रूप से खपाने के लिए लाई गई थी।

आबकारी एक्ट के तहत 3 आरोपी गिरफ्तार : पुलिस तीनों आरोपियों और गाड़ी को थाने ले आई और उनके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में पुरानी पापन निवासी विनोद पिता लखनलाल कीर (28) और दीपक सिंह कीर (25) शामिल हैं। इनके अलावा नई पापन (थाना शिवपुर) निवासी तीसरे आरोपी सुभाष पिता रमेश कीर (26) को भी पकड़ा गया है।

एसआई बोले- तीनों को कोर्ट पेश किया जाएगा : मामले की जानकारी देते हुए एसआई महेश जाट ने बताया, 'गाड़ी से 6 पेटी शराब मिली है। जिसकी कीमत 27हजार रुपए है।' उन्होंने आगे कहा, 'शराब कहा से लेकर आएं। आरोपी स्पष्ट नहीं बता रहे। तीनों को कोर्ट पेश किया जाएगा। '

बड़वानी की छात्रा का शव मिला,पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाया

मीडिया ऑडीटर, खरगोन (निप्र)। खरगोन शहर के कुंदा नगर स्थित निर्भया हॉस्टल में सोमवार रात छात्रा का शव कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला। छात्रा की पहचान 21 वर्षीय रोशनी सोलंकी के रूप में हुई है, छात्रा बड़वानी जिले की वरला तहसील के निरगुडिया गांव की रहने वाली थी। वह खरगोन में रहकर बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी।

रूम पार्टनर ने फंदे पर लटका देखा : घटना का पता तब चला जब रात करीब 8 बजे उसकी रूम पार्टनर पूजा ठाकुर कॉलेज से वापस हॉस्टल लौटी। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। दरवाजा खोलने पर रोशनी का शव पंखे से दुपट्टे के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल में हड़कंप मच गया। इसके बाद तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिजन और खरगोन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रूम पार्टनर पूजा ठाकुर ने बताया कि रोशनी एक दिन पहले ही अपने घर से लौटी थी। वह काफी थकी हुई थी और आज कॉलेज भी नहीं गई थी। वहीं मृतक छात्रा के भाई विजय वास्कले ने बताया कि उन्हें अभी तक घटना के कारणों की जानकारी नहीं है। उन्हें शाम को सूचना मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। खरगोन कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वह कल ही घर से लौटी थी। आरंभिक जांच में छात्रा ने सुसाइड किया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

`भूसे से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटीडीजल-भूसा फैला, पेट्रोल पंप-अस्पताल के पास टला बड़ा हादसा

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर के सागर रोड पर सोमवार रात एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। अग्रवाल पेट्रोल पंप और मल्टी सिटी हॉस्पिटल के बीच भूसे से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। यह घटना रात करीब 9 से 10 बजे के बीच पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी के निवास के पास हुई।

अग्रवाल पेट्रोल पंप और अस्पताल के बीच हुआ हादसा : घटना सागर रोड के उस हिस्से में हुई जहां पास ही अग्रवाल पेट्रोल पंप और मल्टी सिटी हॉस्पिटल स्थित हैं। इसी मार्ग से होकर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भूसा लेकर जा रही थी, जो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।हादसे के बाद कुछ समय के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

ट्रॉली में 10 से 12 फीट तक भरा था भूसा : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर की ट्रॉली में करीब 10 से 12 फीट तक भूसा भरा हुआ था। ट्रॉली में अत्यधिक भार होने के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया।

रायसेन में महुआ पेड़ों की गिनती कर नीचे सफाई हुई

वन विभाग ने की आग से बचाव की नई पहल, वन्यजीवों के लिए जल स्रोत किए तैयार

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन में गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने और वन्य प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग ने जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने और गर्मी के दौरान वन्यजीवों को पानी की कमी न हो, इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

वन्यजीवों के लिए बनाए गए 140 नए जल स्रोत : भीषण गर्मी में जंगलों के प्राकृतिक जल स्रोत अक्सर सूख जाते हैं। ऐसी स्थिति में वन्य प्राणियों को पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार वे पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर भी पहुंच जाते हैं।इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने रायसेन वन मंडल की सभी 140 बीट में एक-एक कृत्रिम जल स्रोत यानी सौंसर तैयार किया है। इन सौंसरों के माध्यम से

जंगल के अंदर ही वन्यजीवों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

पुराने जल स्रोतों की भी कराई गई सफाई : नए सौंसर बनाने के साथ ही वन विभाग ने पहले से मौजूद जल स्रोतों की भी देखभाल की है। विभाग ने जंगलों में मौजूद करीब 150 पुराने जल स्रोतों की सफाई कराई है। इसका उद्देश्य यह है कि गर्मी के मौसम में इन सभी जल स्रोतों में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहे और जंगल में रहने वाले जानवरों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

महुआ पेड़ों के नीचे चलाया गया सफाई अभियान : वनों को आग से बचाने के लिए इस बार वन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। जंगलों में महुआ बीनने के दौरान कई बार लोग सफाई करने के लिए आग लगा देते हैं, जिससे आग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या को देखते हुए वन विभाग ने महुआ के पेड़ों की गिनती कर उनके नीचे विशेष सफाई अभियान चलाया है। पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियों और अन्य ज्वलनशील सामग्री को हटाया जा रहा है, ताकि महुआ बीनने वालों को आग लगाने की जरूरत न पड़े और जंगल सुरक्षित रह सके।

रायसेन जंगल में कई दुर्लभ वन्य प्राणी : रायसेन वन मंडल कई महत्वपूर्ण और दुर्लभ वन्य प्राणियों का निवास स्थान माना जाता है। यहां बाघ, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, हिरण और सांभर जैसे कई वन्यजीव पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में जब प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं, तब इन जानवरों को पानी की तलाश में काफी दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे में नए जल स्रोत तैयार करने से उन्हें जंगल के भीतर ही पानी उपलब्ध हो सकेगा।

जरूरत पड़ने पर टैंकर से भरा जाएगा पानी : वन विभाग ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि किसी सौंसर में पानी की कमी हो जाती है, तो वहां टैंकर के माध्यम से पानी भरवाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गर्मी के पूरे मौसम में जल स्रोतों में पानी बना रहे और वन्य प्राणियों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।

जंगल की आग रोकने के लिए जागरूकता अभियान : वन विभाग केवल जंगल के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चला रहा है। ग्रामीणों को जंगल में आग लगने के खतरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके लिए गांवों में दीवार लेखन कराया जा रहा है और पोस्टर-बैनर लगाए जा रहे हैं। इन पर जंगलों को आग से बचाने से संबंधित संदेश लिखे गए हैं, ताकि लोग जागरूक हों और जंगलों की सुरक्षा में सहयोग करें।

एसडीओ ने बताई विभाग की तैयारी : वन विभाग के मंडल के एसडीओ सुधीर पटले ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए विभाग ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि जंगल की आग इस मौसम में सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए महुआ के पेड़ों की गिनती के साथ उनके नीचे सफाई कराई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की कोशिश है।

गैस की किल्लत में देशी भट्टियों पर बनेगा भोजन, गुड़ी पड़वा पर होगा हजारों लोगों का सामूहिक भोज

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम में गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष के अवसर पर रतलाम में अनेक समाज द्वारा सामूहिक भोज का आयोजन किया जाएगा। गैस की किल्लत के चलते भोजन बनाने के लिए कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत बनी हुई है। ऐसे में 'श्री ओसवाल पंचाग बड़े साथ' समाज द्वारा रसोई बनाने में देशी भट्टियों का उपयोग किया जाएगा। 10 हजार लोगों का भोजन पारंपरिक देशी भट्टियों पर बनाया जाएगा। भट्टियों को बनाने की शुरूआत अभी से हो चुकी है।

गुड़ी पड़वा पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। 'श्री ओसवाल पंचाग बड़े साथ' द्वारा आंबेडकर मैदान में हर साल की तरह इस साल भी समाज की सामूहिक गोठ का आयोजन किया जा रहा है। इस गोठ में सर्व जैन समाज के लोग परिवार के साथ शामिल होते है।

पिछले करीब 50 सालों से यह आयोजन होता है। इस बार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण समाज ने देश हित में निर्णय लेते हुए फैसला लिया है कि लकड़ी व कंडे से भोजन बनाया जाएगा। इसके लिए आयोजन स्थल पर जमीन को खोद कर गड्‌ढा कर मिट्?टी की पारंपरिक देशी भट्टियां बनाई जा रही है। इन्हीं भट्टियों पर भोजन बनाया जाएगा।

700 से अधिक कार्यकर्ता देते है सेवा : आयोजन को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। 700 से 800 कार्यकर्ता अपनी सेवा देते है।

कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावानों. आयोजन में हमेशा सेवा देने वाले समाज के वरिष्ठों का भी सम्मान किया जाएगा। गोठ संयोजक ललित कोठारी ने बताया कि गैस की किल्लत के चलते 10 हजार लोगों का भोजन देशी पारंपरिक भट्टियों पर बनाया जाएगा।

भट्टियों के बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। प्रितेश गादिया ने बताया समाजजनों ने देशहित में निर्णय लेते हुए पारंपरिक रूप से भोजन बनाने की तैयारी की है। पूर्व के सालों में भी भट्?टी पर भोजन बनाया जाता था। फिर गैस पर भोजना बनाया जाने लगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 4 भट्टियां बनाई जा रही है। जिस पर भोजन तैयार किया जाएगा। देशी भट्?टी में लकड़ी व कंडे का उपयोग किया जाएगा। भोजन में लड्?डू, बाफले, दाल, चावल. भजिए, चटनी बनाई जाएगी।

सीहोर में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो दिनों से चल रहे इस अभियान के तहत विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों, होटलों और दुकानों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान कई स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया, जिन्हें जब्त किया गया है।

भैरूंदा में 8 गैस सिलेंडर जब्त : इसी क्रम में भैरूंदा क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने 10 दुकानों और प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी प्रकाश यादव और खाद्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई।

बुधनी में 12 सिलेंडर पकड़े : इसी तरह बुधनी क्षेत्र में भी खाद्य विभाग की टीम ने 7 दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान यहां से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। बुधनी में यह कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी प्रकाश यादव और मृगी अग्रवाल सहित खाद्य विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने की।

अभियान जारी रहेगा : जिला आपूर्ति अधिकारी रेशमा भामोर ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति भी सामान्य रूप से जारी है।

गांजा तस्करी मामले में फरार आरोपी जबलपुर से गिरफ्तारसागर से देवरी बेचने ले जा रहे थे

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर की देवरी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को जबलपुर के कटंगी से गिरफ्तार किया है। थाने लाकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसके एक साथी को 3 किलो 360 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। पुलिस के अनुसार, 11 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सागर की ओर से अवैध रूप से गांजा देवरी लाया जा रहा है। सूचना मिले ही पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना की गई। टीम ने नेशनल हाईवे-44 पर स्थित मीरा ढाबा ओवर ब्रिज के पास चेकिंग लगाई।

पुलिस ने 3 किलो 360 ग्राम गांजा किया था जब्त : इसी दौरान मुखबिर के बतायानुसार बाइक क्रमांक एमपी

15 एमपी 4451 आते हुए नजर आई। पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। तभी बाइक पर पीछे बैठा आरोपी कूदकर खेतों की ओर भागा।

जवानों ने पीछा किया। लेकिन पकड़ नहीं पाए। लेकिन बाइक चला रहे आरोपी जसमत पिता सुम्मेर सिंह कुचबंदिया उम्र 40 साल निवासी नई गल्ला मंडी के पास मोतीनगर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से बैग में रखा 3 किलो 360 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया।

कटंगी में लोकेशन मिली तो पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा : फरार आरोपी विष्णु उर्फ कुक्कर उर्फ अर्जुन पिता राजकुमार कुचबंदिया निवासी ठाकुर बाबा मंदिर के पास मोतीनगर की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्य जुटाए।

जिसके आधार पर आरोपी की लोकेशन जबलपुर के कटंगी में मिली। टीम जबलपुर रवाना हुई और लोकेशन के आधार पर दबिश देकर आरोपी विष्णु कुचबंदिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटनाक्रम के बाद से ससुराल में छिपा था। देवरी थाना प्रभारी हरिराम मानकर ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने लाकर उससे गांजे के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

विदिशा में ट्रक और लोडिंग ऑटो की टक्कर घायल हुआ ऑटो चालक

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। विदिशा में महाराजा खेत सिंह खंगार प्रतिमा के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अंगूर से भरे लोडिंग ऑटो को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो चालक घायल हो गया और सड़क पर गिरे अंगूरों को लोगों ने लूट लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अंगूर से भरा लोडिंग ऑटो भोपाल की ओर से आ रहा था और फ्लाईओवर से गुजर रहा था। इसी दौरान मिर्जापुर की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक गलत दिशा में आ गया और उसने ऑटो को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में लोडिंग ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। घटना मंगलवार दोपहर की है। दुर्घटना के बाद ऑटो में भरे अंगूर सड़क पर

चारों तरफ बिखर गए। सड़क पर अंगूर बिखरे देखकर राहगीरों और आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें लूटना शुरू कर दिया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घायल ऑटो चालक को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

देह व्यापार मामले में चार आरोपियों को सजा, बुरहानपुर कोर्ट का फैसला

मीडिया ऑडीटर, बुरहानपुर (निप्र)। बुरहानपुर में अनैतिक देह व्यापार के मामले में कोर्ट ने सोमवार को चार आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है। इन आरोपियों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं, जिन्हें पुलिस की दबिश के बाद पकड़ा गया था। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल ने बताया कि 13 अगस्त 2023 को शिकारपुरा थाने में पदस्थ विवेचना अधिकारी कमल पंवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिकारपुरा क्षेत्र की एक गली में देह व्यापार चल रहा है।

इस सूचना पर आरक्षक विजय को सिविल ड्रेस में मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम, जिसमें उपनिरीक्षक सखाराम पगारे, अर्चना चौहान, विजय पाटीदार और आरक्षक ज्योति शामिल थे, शिकारपुरा में एक मकान के पीछे पहुंची। खिड़की की दरार से देखने पर अंदर

सिविल ड्रेस में गए पुलिसकर्मी विजय से एक महिला बातचीत करती और उसे नोट देती दिखी।

पूछताछ में गलत काम की बात स्वीकारी : इसके बाद टीम और पंचों ने मकान का दरवाजा खटखटाया। वहां मौजूद एक महिला से पूछताछ की गई। घर के दूसरे कमरों में दो अन्य महिलाएं और एक पुरुष पलंग पर संदिग्ध अवस्था में अर्धनग्न पाए गए। पुरुष आरोपी ने अपना नाम मूलचंद पिता बजरंग लाल बताया। पूछताछ में मूलचंद ने 500-500 रुपए लेकर गलत काम करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

सभी दोषियों को सजा मिली : अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

पहली महिला आरोपी को धारा 3 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में एक वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपए का अर्थदंड, धारा 4 में छह माह का साधारण कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड, तथा धारा 5 में तीन वर्ष का कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। दूसरी महिला आरोपी को धारा 4 में छह माह का कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड दिया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल ने बताया कि 13 अगस्त 2023 को शिकारपुरा थाने में पदस्थ विवेचना अधिकारी कमल पंवार को मुखबिर से सूचना मिली थी तीसरी महिला आरोपी को धारा 4 में छह माह का साधारण कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड मिला।

पुरुष आरोपी मूलचंद को धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में तीन वर्ष का साधारण कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल, सुश्री उषा इंगले, राधेश्याम वास्केल द्वारा की गई जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपियों को दंडित किया गया।

'मैं वनडे कभी समझ नहीं पाया'

सूर्यकुमार यादव का ODI करियर खत्म?

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वनडे क्रिकेट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि वह कभी इस फॉर्मेट में खुद को सेट नहीं कर पाए। उनका मानना है कि वनडे को वह कभी समझ नहीं पाए। इससे हिंट भी मिला है कि अब शायद उनका वनडे करियर खत्म भी मान सकते हैं। वहीं टेस्ट क्रिकेट खेलने की उन्होंने इच्छा भी जताई है। उनका कहना है कि वह टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वहीं सूर्या के वनडे करियर की बात करें तो वह 37 मैच भारत के लिए खेले और 35 पारियों में सिर्फ 773 रन ही बनाए। उनका औसत 25.7 का है और इसमें चार अर्धशतक शामिल हैं। आखिरी बार वह 2023 वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर 2023 को एकदिवसीय मुकाबला खेले थे। अब उनकी वनडे टीम में वापसी उनकी उम्र और पिछले प्रदर्शन को देखते मुश्किल लग रही है।

सूर्यकुमार यादव ने पीटीआई के साथ एक विशेष पॉडकास्ट में बात करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वह अब क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी टी20 के उस्ताद बन चुके हैं और इसे खेलने में सहज महसूस करते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट न खेलने की अपनी निराशा के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने याद दिलाया कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेले थे जिसमें वह केवल एक पारी खेल पाए थे। सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'आपकी किस्मत में जो लिखा होता है, आपको वही मिलता है। मैंने भी लाल गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 10-12 साल तक रणजी ट्रॉफी खेली। मैंने मुंबई में लाल गेंद से बहुत क्रिकेट खेली है क्योंकि अगर आप मुंबई में पले बढ़े होते हैं तो आप लाल गेंद से ही शुरुआत करते हैं, इसलिए सब कुछ लाल गेंद के इर्द-गिर्द ही घूमता है। लेकिन धीरे-धीरे जब हमने सफेद गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू की तो मेरा झुकाव थोड़ा उसकी तरफ हो गया। '

वनडे क्रिकेट के भविष्य पर दिया बयान: सूर्यकुमार यादव से जब पूछा गया कि ऐसे ही समय में जब टी20 कम समय में फैंस को अधिक रोमांचित करता है और टेस्ट क्रिकेट उन्हें पारंपरिक संतुष्टि देता है तो क्या वनडे का कोई भविष्य है? उन्होंने कूटनीतिक रुख अपनाते हुए वनडे को बहुत अधिक खारिज किए बिना उसको उचित सम्मान दिया। वनडे में द्विपक्षीय श्रृंखलाओं की संख्या लगातार घट रही है जो इस फॉर्मेट के पतन का संकेत दे रही है और यही आलम रहा तो वनडे क्रिकेट का अंत हो सकता है। सूर्यकुमार ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने वनडे क्रिकेट को जितना करीब से अनुभव किया है और देखा है, यह एक ऐसा प्रारूप है जहां आपको तीन अलग-अलग तरीकों से बल्लेबाजी करनी पड़ती है। कभी-कभी अगर आप जल्दी बल्लेबाजी करने जाते हैं, अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो आपको टेस्ट क्रिकेट की तरह बल्लेबाजी करनी पड़ती है। ' उन्होंने कहा, 'फिर आपको वनडे की तरह अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होती है और पारी के आखिरी ओवरों में टी20 प्रारूप की तरह बल्लेबाजी करनी होती है। इसलिए यह एक ऐसा प्रारूप है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। मैंने इसे खेलने की पूरी कोशिश की लेकिन यह चुनौती पूर्ण प्रारूप है। ' सूर्यकुमार यादव ने वनडे विश्व कप 2023 के दौरान की गई तैयारी और माहौल को भी याद किया। उन्होंने कहा, 'जब मैं 2023 वनडे विश्व कप के लिए टीम के साथ था और मैं उसमें खेला था तब उस प्रारूप का माहौल, फाइनल से पहले की तैयारियां, वह सब 2026 और 2024 के टी20 विश्व कप में खेले गए मैचों से बिलकुल अलग था। इसलिए, इसका आकर्षण अलग है। वनडे क्रिकेट का भी अपना अलग आकर्षण है, टी20 का तो और भी अलग।

वनडे में निराशा, टेस्ट खेलने की इच्छा

उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद मैं इस फॉर्मेट (टी20) में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने वनडे (50 ओवर की क्रिकेट) में भी अच्छा खेलने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। टी20 क्रिकेट में जैसा चल रहा था, उसमें अपना हाथ सेट हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं।' सूर्यकुमार से जब पूछा गया कि अगर उन्हें मौका मिले तो क्या वह टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगे? उन्होंने सीधा जवाब दिया, 'मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 2010-11 से 2020 तक लाल गेंद से काफी क्रिकेट खेली है। दस साल तक लाल गेंद से खेलना बहुत लंबा समय होता है। मुझे इस प्रारूप से बेहद लगाव था। स्वाभाविक है कि अगर मौका मिले तो फिर कौन टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहेगा। ' टेस्ट में उनका एकमात्र अनुभव 2023 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया मैच था, जब उन्होंने एक पारी में आठ रन बनाए थे। उसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्व कप के फाइनल में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 28 गेंदों में 18 रन बनाए। भारत फाइनल हार गया और सूर्यकुमार उसके बाद इस प्रारूप में कभी नहीं खेल पाए।

शोएब अतर को मिला मुंहतोड़ जवाब, भारत की जीत के बाद दिया था 'अमीर बच्चे' वाला बेतुका बयान

'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे'

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टीम ने 8 मार्च को जब तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता था, तो उस वक्त कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसी लिस्ट में एक नाम शोएब अख्तर का भी था, जिन्होंने एक बेतुका बयान दिया था। शोएब ने कहा था कि क्रिकेट को खत्म किया जा रहा है। भारत के हिसाब से सब हो रहा है और भारतीय टीम को उन्होंने मोहल्ले का अमीर बच्चा भी बताया था। अब भारत के पूर्व क्रिकेटर ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। शोएब अख्तर का कहना साफ था कि भारत कुछ देशों को अपने घर बुलाता है और खुद जीत जाता है। ऐसे क्रिकेट को खत्म किया जा रहा है। अब इस बयान पर आकाश चोपड़ा ने रावलपिंडी एक्सप्रेस को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, 'देखिए इंडिया सेंट्रिक यह खेल (क्रिकेट) तो अभी रहेगा और इस वजह से क्योंकि देखने वाली जनसंख्या यहां है। खेल के अंदर जो रेवेन्यू है जो यहां से आता है, यही दो चीजें हैं जिनमें सेंट्रिक रहने वाली हैं। '

आकाश ने क्रेक्स लाइव पर अपने वीडियो में आगे कहा, 'इसके अलावा जो टीम अच्छा खेलेगी वही ट्रॉफी उठाएगी। जो टीम बेहतर प्रदर्शन करती जाएगी उसका उतना नाम होगा। वर्ल्ड कप के या जितने आईसीसी इवेंट होते हैं वह रोटेशनल प्रक्रिया से होते हैं। ऐसे देखें तो ड्ड्रञ्जष्ट (विश्व टेस्ट चैंपियनशिप) का फाइनल इंग्लैंड में होता है। तीन फाइनल हो गए दो बार हम लंदन जाकर खेले , अगर हम आईसीसी को कंट्रोल करते हैं तो उसे दिल्ली या मुंबई में करवा लेते और हम जीत भी जाते।

'अंगूर खट्टे हैं, या खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे...

भारत के पूर्व टेस्ट ओपनर ने आगे कहा, 'इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम आईसीसी को कंट्रोल कर रहे हैं। पर यह है कि एशियन ब्लॉक इतना बड़ा है कि हर दूसरा, तीसरा आईसीसी इवेंट भारत को मिलेगा भले भारत संयुक्त मेजबान हो, क्योंकि भारत का बोर्ड एक सक्षम बोर्ड है और किसी पर निर्भर नहीं है। आईसीसी का मेन रेवेन्यू जनरेटर भी भारत है। तो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, या खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यह दो हिंदी के मुहावरे हैं शोएब के लिए नहीं कहे रहा उन सभी लोगों के लिए हैं जिन्हें लगता है कि भारत आईसीसी को कंट्रोल कर रहा।

वैभव-यशस्वी ओपनर

हेटमायर, करन, फरेरा भी मौजूद, भारतीय दिग्गज ने IPL 2026 के लिए चुनी RR की खतरनाक प्लेइंग 11

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2026 के पहले चरण का शेड्यूल आ चुका है और लीग का आगाज 28 मार्च से होगा। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना अभियान 30 मार्च से शुरू करेगी। राजस्थान का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। इस सीजन राजस्थान के पास कई धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं। इसको देखते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर ने राजस्थान रॉयल्स की खतरनाक प्लेइंग 11 चुनी है। इस मैच में कई ऐसे खिलाड़ी आमने-सामने होंगे जो अपनी पिछली टीमों के खिलाफ उतरने वाले हैं। संजू सैमसन इस बार पिंक नहीं पीली जर्सी में नजर आएंगे, तो रविंद्र जडेजा पीली से पिंक जर्सी में दिखेंगे। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के सभी खिलाड़ियों के नाम बताए हैं। उनकी प्लेइंग 11 में कई धाकड़ नाम शामिल हैं। क्रेक्स लाइव पर वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग 11 चुनी है। आकाश ने अपनी प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर ध्रुव जुरेल को चुना है। वहीं नंबर 4 पर कप्तान रियान पराग को उन्होंने जगह दी है। इसके अलावा नंबर 5 के लिए सैम करन, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 7 पर शिमरोन हेटमायर को चुना है। साथ ही डोनोवन फरेरा भी टीम के पास हैं जो 8वें नंबर पर बल्लेबाजी में धूम धड़ाका मचा सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं।

यह है राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2026 का पूरा स्क्वाड

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेन मफाका, नांद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा, डोनोवोन फरेरा, सैम करन, रवि बिश्नोई, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, यश राज पुंज, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन, बृजेश शर्मा, अमन राव पेराला।

इशान किशन बन सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, पैट कमिंस के खेलने पर सस्पेंस

नई दिल्ली, एजेंसी। इशान किशन के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 शानदार रहा था। वह 317 रन बनाकर भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उससे पहले उनकी लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी हुई थी। उन्होंने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी कप्तानी में पहली बार झारखंड को चैंपियन भी बनाया था। अब खबरें हैं कि वह आईपीएल में भी सनराइजर्स हैदराबाद की कमान संभाल सकते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में कर सकते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पीठ की चोट से रिकवर कर रहे हैं और इसी कारण वह टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेले थे। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स से यह जानकारी सामने आई है कि अभिषेक शर्मा कुछ मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन अब इशान का नाम सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार पैट कमिंस कुछ मैचों के लिए टूर्नामेंट से बाहर रहे सकते हैं। हैदराबाद की टीम अपना पहला मैच सीजन के पहले दिन 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भी होगा। कमिंस की वापसी कब होगी इसका कोई अपडेट नहीं है। अगर कमिंस नहीं लौटते हैं तो इशान ही पूरे सीजन टीम की कमान संभाल सकते हैं।

इशान किशन का कैसा है आईपीएल रिकॉर्ड

इशान किशन के आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो उनके नाम 119 मुकाबलों में 2998 रन दर्ज हैं। उनका औसत 29 से अधिक और स्ट्राइक रेट 137 से ऊपर का है। उनके नाम एक शतक, 17 अर्धशतक दर्ज हैं। इशान ने आईपीएल में अभी तक 288 चौके और 134 छक्के लगाए हैं। वहीं वह एक बेहतरीन विकेटकीपर भी हैं और उन्होंने 59 कैच व 5 स्टंपिंग भी आईपीएल में की हैं। इशान किशन को आईपीएल 2025 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ की कीमत पर खरीदा था। इशान का प्रदर्शन भी अच्छा रहा था। उन्होंने पिछले सीजन 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से एक शतक और एक अर्धशतक समेत 354 रन बनाए थे। इस सीजन उनका आत्मविश्वास विश्व विजेता बनने और भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद चरम पर होगा। अगर वह बतौर कप्तान शानदार प्रदर्शन करते हैं तो यह हैदराबाद के लिए एक युवा कप्तान के नेतृत्व में नई शुरुआत हो सकती है।

रोहित शर्मा नंबर 1, संजू सैमसन भी लिस्ट का हिस्सा

ये हैं IPL में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होगा। पहला मैच आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। इसी बीच आपको आईपीएल इतिहास से जुड़ा एक खास आंकड़ा बताता हैं। यह रिकॉर्ड इंडियन प्रीमियर लीग में 200 प्लस या कहें 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों का। इस लिस्ट में हिटमैन रोहित शर्मा टॉप पर हैं। कुल छह भारतीय खिलाड़ी ही आईपीएल में अभी तक 200 प्लस छक्के लगा पाए हैं। भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने आईपीएल में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। उनसे ऊपर सिर्फ क्रिस गेल हैं जिनके नाम 357 छक्के दर्ज हैं। जबकि रोहित भारतीयों के मामले में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। संजू इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जलवा दिखाते नजर आएंगे। जबकि रोहित और संजू के अलावा इस लिस्ट में किंग कोहली भी मौजूद हैं। कोहली और रोहित के बीच सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में आगामी सीजन में टक्कर भी दिख सकती है। वहीं रोहित एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में 300 छक्कों का आंकड़ा पार किया है।

आईपीएल में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

खिलाड़ी	मैच	पारी	छक्के
रोहित शर्मा	272	267	302
विराट कोहली	267	259	291
एमएस धोनी	278	242	264
संजू सैमसन	177	172	219
केएल राहुल	145	136	208
सुरेश रैना	205	200	203

आईपीएल 2026 की बात करें तो अभी सिर्फ पहले 20 मैचों का ही शेड्यूल सामने आया है। इस पहले चरण में अभी प्रत्येक टीम के शुरुआती चार मैचों की लिस्ट ही जारी हुई है। बाकी का शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। भारत के कई राज्यों में चुनाव के कारण इसमें देरी हुई। अब चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं तो जल्द ही बचा हुआ शेड्यूल भी जारी हो जाएगा।

'जब वह मेरी जगह होंगे तब पूछूंगा ' गौतम गंभीर ने एमएस धोनी की मजाकिया पोस्ट पर फिर दिया अटपटा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच खास बातचीत नहीं होती है। अक्सर गंभीर और माही के बीच सोशल मीडिया पर विवाद की भी खबरें आती हैं, लेकिन जब टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता तो एमएस धोनी ने मजाकिया पोस्ट करके उनकी तरफ से किसी भी तरह के विवाद की अटकलों को खत्म कर दिया। मगर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर लगातार माही के मजाकिया पोस्ट पर अटपटा बयान दे रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही गौतम गंभीर की तरफ से रिएक्शन आया है। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद एमएस धोनी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा था और उसमें यह भी कहा था कि, कोच साहब स्माइल आपके ऊपर अच्छी लगती है। उसके बाद गंभीर ने भी चार शब्दों में रिप्लाई किया था। फिर एक पॉडकास्ट में इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, तौर कोच कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं।

BCA चुनाव में हाईकोर्ट की एंट्री

नौ साल की 'इनिंग' पड़ी भारी! पूर्व क्रिकेटर समेत 4 उम्मीदवार अयोग्य घोषित

नई दिल्ली, एजेंसी। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में उस वक्त बड़ा मोड़ आ गया जब गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर समेत चार उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया। हाई कोर्ट ने नौ साल के कुल कार्यकाल और अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए चुनाव अधिकारी के फैसले को रद्द कर दिया। इस आदेश के बाद बीसीए (क्ष्ट) चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया है। अब आगे की प्रक्रिया नए निर्देशों के तहत पूरी की जाएगी।

गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार 16 मार्च 2026 को भारत के पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे और तीन अन्य को बीसीए का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें विभिन्न पदों के लिए उनके नामांकन पत्रों को स्वीकार किया गया था। न्यायमूर्ति निरल आर मेहता ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया था जिसमें क्रिकेट संस्था में उम्मीदवारों के नौ साल का कुल कार्यकाल पूरा करने और अनिवार्य ब्रेक (कूलिंग ऑफ अवधि) का जिक्र था।

अदालत ने चुनाव अधिकारी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने पदाधिकारियों के पद के लिए किरण मोरे, अमूल जिकर, अनंत इंदुलकर और अमर पेटीवाले के नामांकन पत्र स्वीकार किए थे और 22 फरवरी को जारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची में उनके नाम प्रकाशित किए थे। तीन महीनों में दहेज मृत्यु के 510 में से 508 आरोपियों को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ की कड़ी टिप्पणी गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्रतिवादी बीसीए के पदाधिकारियों के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, नतीजतन निर्वाचन अधिकारी द्वारा पदाधिकारियों के पद के लिए प्रतिवादियों के नामांकन पत्र स्वीकार करने और 22 फरवरी को जारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची में उनके नाम प्रकाशित करने का फैसला रद्द किया जाता है।

गुजरात हाई कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और कानून तथा आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार परिणाम घोषित करें। गुजरात हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों के अंतरिम व्यवस्था के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें अदालत के आदेश को लेकर अपील करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करें सभी खेल स्थलों को: यशवंत कुमार

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आज रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालनालय में आयोजित बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं में लगे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त समय रहते सभी इंतजाम पुख्ता रूप से सुनिश्चित करने को कहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने बैठक में कहा कि खेलो इंडिया

नेशनल ट्राइबल गेम्स राष्ट्रीय महत्व और छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन है। इससे संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त, पुख्ता एवं चौकचौबंद होने चाहिए।

उन्होंने सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाते हुए पर्याप्त समय रहते सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन के लिए चिन्हांकित सभी खेल स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने को कहा।

विभागीय सचिव कुमार ने खेल मैदानों, खिलाड़ियों के ठहरने की जगहों, विमानतल और रेल्वे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में स्टॉफ तैनात करने के निर्देश दिए, ताकि आयोजन में भाग लेने पहुंचने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों को ट्राइबल गेम्स में हिस्सेदारी के लिए विभिन्न राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले प्रतिभागियों को यहां की संस्कृति, पुरातत्व एवं कला की जानकारी देने के साथ ही पर्यटन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा।

कुमार ने आयोजन में विभिन्न भाषाओं वाले राज्यों की भागीदारी को देखते हुए उन भाषाओं के जानकार अधिकारियों-कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनूजा सलाम और उप संचालक रश्मि ठाकुर सहित रायपुर जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, परिवहन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, जनसंपर्क, स्वास्थ्य विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। अंबिकापुर और जगदलपुर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए।

'मरीजों की सेहत से समझौता नहीं' - स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

स्वास्थ्य मंत्री का मनेन्द्रगढ़ सिविल अस्पताल में औचक निरीक्षण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रविवार को शासकीय सिविल अस्पताल मनेन्द्रगढ़ का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में उपचार व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता, साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने डॉक्टरों एवं अस्पताल प्रबंधन से आवश्यक जानकारी लेते हुए मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि मरीजों को समय पर इलाज और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का औपचारिक निरीक्षण किया। रविवार होने के कारण ओपीडी बंद थी, इसके बावजूद उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और साफ-सफाई को लेकर संतोष व्यक्त किया। सीएचएमओ डॉ. खरे ने बताया कि अस्पताल परिसर में अनावश्यक रूप से आने वाले अवांछनीय तत्वों की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई है, जो दो शिफ्टों में तैनात रहते हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में जब मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होगा, तब सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इस दौरान सीएचएमओ डॉ. अविनाश खरे, स्वप्निल तिवारी, मंडल अध्यक्ष रवि वर्मा सहित अस्पताल के चिकित्सक, अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित रहे।

बाघापारा तालाब के जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4.98 करोड़ रुपये स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कांकेर जिले के विकासखण्ड-कांकेर के बाघापारा तालाब का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 98 लाख 54 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई (289 हेक्टेयर) में 20 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 56 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 345 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के कार्य कराने मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग जगदलपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

रामजीवन देवांगन ने राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का पदभार ग्रहण किया

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रामजीवन देवांगन ने माना कैम्प, रायपुर स्थित कार्यालय में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ के पद का कार्यभार ग्रहण किया। देवांगन न्यायिक क्षेत्र में लंबे समय तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं और उन्हें प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यों का व्यापक अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात देवांगन ने कहा कि राज्य में दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा, सम्मान और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा तथा दिव्यांगजनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय सक्रिय रूप से कार्य करेगा। साथ ही दिव्यांगजनों से प्राप्त शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए भी विशेष पहल की जाएगी।

डिजिटल सुशासन और शासकीय खरीद में पारदर्शिता की ओर सशक्त कदम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित न्यू सर्किट हाउस में सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा विकसित इलेक्ट्रानिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। चिप्स एवं एन.आई.सी. के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में शासकीय खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य के समस्त विभागों को नवीन प्रोक्योरमेंट प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाना है। कार्यशाला के प्रथम दिन लोक कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, गृहनिर्माण विभाग,पर्यटन विभाग सहित 50 विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हुए, जिन्हें एन.आई.सी. नई दिल्ली से उषा सक्सेना, उप-महासंचालक के नेतृत्व में आये पांच सदस्यी दल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक

ने बताया वर्तमान ई-खरीद प्रणाली दस वर्षों से कार्यशील है, वर्तमान प्रोक्योरमेंट प्रणाली से एन.आई.सी. द्वारा विकसित नवीन जेपनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ओर माइग्रेशन प्रदेश के लिए एक नई और सशक्त शुरुआत है। मलिक ने इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जेपनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने हेतु योगदान के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य के विभिन्न विभागों के प्रोक्योरममेंट से सम्बन्धित नोडल अधिकारीयों को नवीन प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली की उप-महासंचालक एवं ई-प्रोक्योरमेंट ग्रुप प्रमुख उषा सक्सेना ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल सुशासन नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि टेंडर में सबसे ज़रूरी तत्व पारदर्शिता, दक्षता और समानता हैं, यानि टेंडर प्रक्रिया में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध रहना। एन.आई.सी. का जेपनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम इन सभी ज़रूरी मानकों को पूर्ण करता है। उषा सक्सेना ने बताया कि जेपनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रतिदिन 5-6 हज़ार निविदाएं हैंडल की जा रही हैं। इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला के द्वितीय प्रशिक्षण सत्र में ई-खरीद से संबंधित शासकीय नीतियों, बेस्ट प्रैक्टिस, सॉफ्टवेयर फीचर के विषय में विस्तार से बताया जायेगा।

अपने स्वागत उद्बोधन में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी टी. एन. सिंह ने कहा कि जेपनिक प्रोक्योरमेंट प्रणाली ई-सुशासन की दिशा में नया कदम है, यह एक कॉम्प्रेहेंसिव ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली है। इस स्केलेबल प्रणाली को राज्य की ज़रूरतों के अनुरूप री-स्ट्रक्चर और कस्टमाइज़ किया गया है। विभिन्न सुरक्षा फीचरों से सुसज्जित यह सिस्टम शासन की हर ज़रूरतों और चुनौतियों को कवर करता है।

मनखे-मनखे एक समान के सिद्धांत पर चल रही है हमारी सरकार : गुरु खुशवंत साहेब

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के विभाग के लिए 12 हजार 970 करोड़ रूपए की अनुदान मांगें विधानसभा में आज पारित कर दी गई है। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े अनुसूचित जाति वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रातः स्मरणीय, विश्ववंदनीय परम् पूज्य बाबा गुरु घासीदास बाबा जी के मनखे-मनखे एक समान के संदेश पर चल रही है। इसी कड़ी में सरकार अनुसूचित जातियों की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए उनके समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मंत्री साहेब ने बताया कि अनुसूचित जाति कल्याण हेतु 7 करोड़ 15 लाख 39 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 565 करोड़ 89 लाख 8 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल बजट 573 करोड़ 4 लाख 47 हजार रुपये बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुख्य बजट 531 करोड़ 17 लाख 64 हजार रुपये की तुलना में 7.88 प्रतिशत अधिक है।

अनुसूचित जाति उपयोजना में बड़ा प्रावधान: मंत्री गुरू खुशवंत साहेब ने बताया कि राज्य के मुख्य बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से 12,970 करोड़ 2 लाख 45 हजार रुपए का समेकित बजट प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से सुरक्षित मातृत्व को मिल रहा संबल

बलरामपुर की शशी को मिला पोषण और स्वास्थ्य जांच का सहारा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। गर्भावस्था के दौरान माताओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना प्रभावी साबित हो रही है। योजना के माध्यम से प्रदेश की हजारों महिलाओं को सहायता मिल रही है, जिससे सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के विकासखंड राजपुर अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र कोडाकुपारा की निवासी शशी को योजना से बड़ी राहत मिली। सीमित आय वाले परिवार से संबंध रखने वाली शशी के लिए गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। मजदूरी पर निर्भर रहने के कारण अतिरिक्त खर्च की चिंता बनी रहती थी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत उन्हें कुल

5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिसमें पहली किश्त के रूप में 3000 रुपये और दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये उनके खाते में जमा किए गए। इस सहायता राशि से उन्होंने पौष्टिक आहार लिया और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन और बेहतर देखभाल के परिणामस्वरूप उन्होंने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया, जिसका जन्म के समय वजन 2.8 किलोग्राम रहा। वर्तमान में नियमित स्तनपान और संतुलित देखभाल से शिशु का विकास स्वस्थ रूप से हो रहा है और परिवार में खुशी का माहौल है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि फरवरी 2026 की स्टेट-वाइज राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य ने 93.37 प्रतिशत नामांकन, 83.87 प्रतिशत स्वीकृति दर और 93.95 प्रतिशत शिकायतों के त्वरित समाधान के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक राज्य में 1 लाख 86 हजार 586 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया जा चुका है और 72 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपये की राशि सीधे हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।

प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों ने लघु वनोपजों से उत्पाद बनाने की प्रक्रिया देखी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के जंगलों में भारतीय वन सेवा (IFS) के वर्ष 2025-26 बैच के 133 प्रशिक्षु अधिकारियों ने मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन प्रबंधन तथा लघु वनोपज के उत्पादन, प्रसंस्करण से जुड़ी तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव के सहयोग तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को छत्तीसगढ़ की वन प्रबंधन प्रणाली और जल संरक्षण कार्यों का

व्यावहारिक अध्ययन कराया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून से आए प्रशिक्षु अधिकारियों ने 8 से 15 मार्च 2026 तक धमतरी वनमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने पम्पारनाला, कांसानाला और साजापानी नाला जैसे क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण तथा वाटरशेड प्रबंधन से जुड़े कार्यों का अध्ययन किया। प्रशिक्षण के अंतिम चरण में अधिकारियों को वैज्ञानिक पद्धति से वृक्षों के सीमांकन, मार्किंग और कटाई की तकनीकी प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

छत्तीसगढ़ के पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल - देशभर के टूर ऑपरेटरों ने देखी छत्तीसगढ़ की अनोखी झलक

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार-प्रसार और राज्य की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर को देश-दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित फेम (FAM) ट्रिप के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों से आए टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंट्स ने बस्तर, मैनपाट और जशपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखा और उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। फेम ट्रिप के दौरान प्रतिनिधियों को बस्तर जिले के विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया साथ ही बोटिंग भी कराई गई, जिसने उनके अनुभव को और रोमांचक बना दिया। इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने चित्रकोट स्थित प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन भी किए। बस्तर की

जीवंत लोक संस्कृति से परिचित कराने के लिए प्रतिनिधियों को यहां के प्रसिद्ध हाट-बाजार भी ले जाया गया, जहां उन्होंने पारंपरिक मुर्गा लड़ाई जैसे स्थानीय सांस्कृतिक आयोजनों को देखा और बस्तर की विशिष्ट जनजातीय परंपराओं को समझा। इस भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों को ऐतिहासिक नगरी बारसूर भी ले जाया गया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध बत्तीसा मंदिर और भगवान गणेश की अद्भुत एवं प्राचीन मूर्तियों का अवलोकन किया। इन ऐतिहासिक धरोहरों ने प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया।

फेम ट्रिप के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बस्तर के कमिश्नर, आईजी और एसपी से भेंट कर क्षेत्र में पर्यटन विकास, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन सुविधाओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रतिनिधियों को मैनपाट के खूबसूरत पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराया गया।

मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 3 हजार 622 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, परिवहन तथा संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के विभागों से संबंधित 3 हजार 622 करोड़ 86 लाख 35 हजार रूपए की अनुदान मांगे विधानसभा में पारित की गई। इसमें वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग लिए 2 हजार 867 करोड़ 30 लाख रूपए, सहकारिता विभाग के लिए 389 करोड़ 40 लाख 85 हजार रूपए, परिवहन विभाग के लिए 243 करोड़ 50 लाख 50 हजार रूपए और राज्य विधानमंडल के लिए 122 करोड़ 65 लाख रूपए शामिल हैं।

मंत्री कश्यप ने अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा वनवासियों की आजीविका को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए आगामी वर्षा ऋतु में लगभग 3.50 करोड़ पौधे रोपने और वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार के लिए 80 करोड़ रुपये और बिगड़े वनों के सुधार के लिए 310 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 की परिकल्पना की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को पूर्ण विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाना है। इसी तरह नदी तटों पर भू-क्षरण रोकने के लिए 7 करोड़ रुपये तथा भू-जल संरक्षण योजना के लिए 120 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए भी 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन में कहा कि वन्यजीव संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए 320.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि बाघ संरक्षण के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर' योजना के तहत 23.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मंत्री कश्यप ने बताया कि दूरस्थ अंचलों में निवासरत वनवासियों को बारहमासी आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वन मार्गों में रपटा पुलपुलिया का निर्माण किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत इस वर्ष 5 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही सड़कें तथा मकान निर्माण के लिए 11 करोड़ रूपए का बजट प्रास्तावित है। इसी तरह काष्ठ एवं बांस कूपों के विदोहन के उपरांत प्राकृतिक पुनरोत्पादन को बढ़ावा देने इस योजना के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वहीं ए.एन.आर. योजनांतर्गत भी 300 करोड़ रूपए का प्रावधान है। इसी तरह वनवासियों को उनके मालिकाना हक की भूमि में ईमारती लकड़ी के विदोहन के लिए 183 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री कश्यप ने बताया कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ई-कुबेर योजना हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी तरह कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को से विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हांकन हेतु चयनित किया गया है। वहीं वन विभाग में मानव संसाधन में वृद्धि करने के लिए वनरक्षकों 1484 एवं सहायक ग्रेड-3 के 50 पदों पर भर्ती की जा रही है।

मंत्री कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में चरणपादुका वितरण योजना को फिर से शुरू किया गया है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 44.25 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है और भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण के मामले में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है।

मंत्री कश्यप ने बताया कि राज्य में जैव विविधता संरक्षण और वेटलैंड विकास को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की जा रही हैं। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एवं भारत वर्ष का 96वाँ रामसर स्थल अधिसूचित किया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से राज्य की जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और जल जीवन के प्रति हमारे सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा